सुविचार

"दो व्यक्तियों ने एक ही सलाखों से बाहर झांका, एक को कीचड़ दिखाई देता है, दूसरे को तारे दिखाई देते हैं।" - फ्रेडरिक लैंगब्रिज

दैनिक इंटीग्रेटेड ट्रेड

डेवलपमेंट सेंटर न्यूज

आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस | 2018 में स्थापित | ITDCNEWS.COM

आरएनआई नं. MPHIN/2018/77221

डाक पंजीयन नं. MP/BHOPAL/4-504/2020-22

वर्ष-5 अंक-179, भोपाल, शनिवार 14 मई 2022, पृष्ठ-8, मूल्य-2 रुपए

5 चरणों में होंगे मप्र पंचायत-निकाय चुनाव

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों (पंचायत और नगरीय निकाय 2022) की तैयारियों शुरू हो गई है।राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि नगरीय निकायों के चुनाव में श्वङ्करूऔर त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनाव में मतपत्र और मतपेटियों का उपयोग किया जाएगा। पंचायतों का चुनाव भी श्वङ्करूसे करवाने पर 3 माह से अधिक समय लगेगा, क्योंकि श्वङ्करूकी संख्या सीमित है। इसलिए मतपेटियों के माध्यम से पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों के चुनाव 2 चरण में और पंचायतों के चुनाव 3 चरण में करवाये जायेंगे। दोनों चुनाव साथ में कराना है, इसलिए ऐसी तैयारी करें कि किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। कोई भी समस्या हो, तो मुझे अथवा सचिव राज्य निर्वाचन आयोग को तुरंत बताएँ। संवेदनशील और अति-संवेदनशील मतदान केन्द्रों की समीक्षा कर जानकारी जल्द आयोग को उपलब्ध कराएँ।

निर्वाचन प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग करें।

बैठक में सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिये चुनाव मोबाइल एप का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। नवीन प्रावधानों के अनुरूप पार्षदों के निर्वाचन व्यय के लेखा का संधारण व्यवस्थित रूप से करवाएँ। रिजर्व ईव्हीएम सुरक्षित तरीके से निर्धारित स्थानों पर ही रखवाएँ। सभी कलेक्टर्स चुनाव सामग्री की उपलब्धता की समीक्षा कर लें। मतदान पेटी का मेंटेनेंस करवा लें। मतपत्र मुद्रण के लिये सभी तैयारियाँ पहले से कर ली जाये।

समुचित सुरक्षा व्यवस्था हो

राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना और अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा से नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में चर्चा की और कहा कि आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिये समुचित सुरक्षा व्यवस्था करें। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान-केन्द्रों पर विशेष ध्यान रखें। कहीं पर भी अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिये। नगरीय निकाय चुनाव 2 चरण और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरण में करवाये जायेंगे। नगरीय निकायों में पार्षदों का चुनाव करवाया जायेगा। महापौर/अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जायेगा।

समय समय पर बैठक आयोजित करें

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने कहा कि रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कर आयोग को सूचित करें। जिम्मेदार अधिकारियों से मतदान केन्द्रों का सत्यापन कराएँ और आवश्यकता अनुसार उनकी मरम्मत करवा लें। राजनैतिक दलों के साथ समय-समय पर बैठक आयोजित करें। मतगणना स्थल का निर्धारण कर आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें। जिला, नगरीय निकाय एवं ब्लाक स्तर पर ट्रेनिंग के लिये मास्टर ट्रेनर्स का चयन कर लें।बैठक में ईव्हीएम, सूचना प्रौद्योगिकी, सामग्री प्रबंधन और प्रशिक्षण के संबंध में भी जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया।

कश्मीरी पंडित की हत्या पर कांग्रेस के मौन से तुष्टिकरण की नीति की खुली पोलः नरोत्तम मिश्रा

भोपाल। प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने आज कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट जी की हत्या पर खुद को कश्मीरी पंडित कहने वाले राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी मौन है। आज कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति और असली चरित्र को पूरा देश देख रहा है। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन नहीं, चिंता शिविर हो रहा है। जहां पार्टी को बचाने और राहुल गांधी जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की चिंता होगी। उन्होंने आगे कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जो भी सच है उसको सामने आना चाहिए। इस विषय पर ओवैसी समेत अन्य लोगों में बौखलाहट और आक्रोश किस बात का है? प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 35 नए केस आए हैं, वहीं 33 मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल एक्टिव केस 232, संक्रमण दर 0.45त्न और रिकवरी रेट 98.70प्रतिशत है। उन्होंने प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक, पद्मविभूषण से सम्मानित गुरुदेव श्री रविशंकर जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि मां पीताम्बरा से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूँ।

सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी

पटना. सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ पटना हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट में उनकी सशरीर पेशी होनी थी, लेकिन, वह कोर्ट में नहीं पहुंचे। इस बात से नाराज होकर पटना हाई कोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तरप्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।

मनरेगा कर्मी अपनी दो सूत्रीय मांगों पर अडिग

रायपुर। मनरेगा कर्मियों के 2 सूत्री मांगों को लेकर 4 अप्रेल से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, इसी बीच रोजगार सहायको के मानदेय में बढ़ोतरी की खबरे प्रसारित हुई। इस दिशा में पहल के लिए छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर अग्निवंशी और कार्यकारी प्रांताध्यक्ष राधेश्याम कुर्रे ने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है, किन्तु यह भी कहा कि हमारी मांग चुनावी जन घोषणा पत्र को आत्मसात करते हुए समस्त मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण एवं नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण करते हुए समस्त मनरेगा कर्मियो पर सिविल सेवा नियम 1966 के साथ पंचायत कर्मी नियमावली लागू किया जावे है, जिसके संबंध में अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है।

कश्मीरी पंडित राहुल भट की हत्या पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी से पूछे सवाल

कश्मीरी पंडित राहुल भट की हत्या पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी से पूछे सवालस्वामी ने ट्वीट कर कहा, %इस्लामी आतंकवादियों द्वारा राहुल भट की हत्या को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, जैसाकि मोदी सरकार अभी कर रही है। हिंदुत्व की बात करने का क्या फायदा जब सरकार डरपोक है और इसका जवाब नहीं दे रही है। क्यों पीएम मोदी केवल जम्मू ही जाते हैं। उन्हें तुरंत श्रीनगर जाना चाहिए। बडगाम में राजस्व विभाग में राहुल भट (35) क्लर्क के पद पर तैनात थे। गुरुवार को दो आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।

कांग्रेस नवसंकल्प शिविर का आगाज, 2024 में सत्ता का सपना देख रही है पार्टी

कांग्रेस के 9 बड़े प्लान- जमीनी कार्यकर्ताओं को इनाम, और परिवारवाद से बनाई दूरी

कांग्रेस नवसंकल्प शिविर का आगाज हो चुका है। गांधी परिवार के तीनों प्रमुख सदस्यों के साथ कांग्रेस के तमाम नेता उदयपुर पहुंच चुके हैं। पहले दिन शुक्रवार को कांग्रेस के महासचिव व राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि शिविर के बाद कांग्रेस पार्टी के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने नवसंकल्प शिविर में किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, उसके बारे में भी बताया। हम अपनी इस खास रिपोर्ट में बता रहे हैं कांग्रेस के उन 9 बड़े प्लान्स के बारे में, जिनके भरोसे पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों के साथ 2024 की सत्ता का सपना देख रही है।

संगठन में होंगे बड़े बदलाव

होटल अरावली ताज में कांग्रेस नेता माकन ने बताया कि संगठन को लेकर बने कांग्रेस के पैनल ने पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन के लिए सुझाव दिए हैं। उन पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के ढांचे में अब तक वही पद चले आ रहे थे जो सालों पहले थे। लेकिन अब उसमें बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक बदलाव किया जा रहा है। कुछ चीजें हमारे संविधान में पहले से थी, लेकिन उनको अमल में नहीं लाया जा सका।

पैराशूट नेताओं की नो एंट्री

माकन ने कहा कि पार्टी एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर काम करेगी। किसी भी नेता का रिश्तेदार, बेटा या बेटी को टिकट तभी मिल सकेगा, जब तक कि वे पांच साल पार्टी में काम नहीं करेंगे। यानी पैराशूट से कोई नेता नहीं उतारा जाएगा।

बूथ और ब्लॉक के बीच होंगे मंडल

भाजपा की तरह ही अब कांग्रेस में भी मंडलों का गठन किया जाएगा। हर पंद्रह बीस बूथों पर एक मंडल होगा। तीन से चार मंडलों पर एक ब्लॉक का गठन किया जाएगा। इसके गठन के लिए भी एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

परमानेंट सर्वे डिपार्टमेंट बनाएंगे

माकन ने बताया कि अक्सर चुनाव के समय ही हम कुछ प्राइवेट एजेंसी से सर्वे करवाते रहे हैं। लेकिन अब तय किया गया है कि कांग्रेस का इंटरनल पब्लिक इनसाइड डिपार्टमेंट होगा। इस डिपार्टमेंट में शामिल लोग लगातार जनता के बीच फीडबैक लेंगे। जनता किन मुद्दों पर क्या चर्चा कर रही है, उसके आधार पर चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी।

रिवार्ड और सजा का प्लान

माकन ने कहा कि जो कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहे हैं, उनको रिवार्ड नहीं दिया जाता है और जो काम नहीं कर रहे हैं या खराब काम कर रहे हैं, उन्हें सजा नहीं मिलती है। इसको लेकर कांग्रेस में असेस्टमेंट विंग बनाने का सुझाव है। यह विंग तय करेगी कि कौन कार्यकर्ता बेहतर काम कर रहा है और उसका क्या रिवॉर्ड देना चाहिए? जो लोग खराब काम या पार्टी के विरोध में काम करेंगे, उन्हें सजा का प्रावधान किया जाएगा।

अनुशासन को मजबूत करेंगे

कांग्रेस के नेता माकन ने कहा कि हम पार्टी में अनुशासन को और मजबूत करेंगे। इसके लिए हर स्तर पर अनुशासन कमेटी बनेगी। शिविर में इस पर चर्चा की जाएगी।

सड़कों पर लगातार हो रहा कार्य, जल्द ही होगा सड़क संबंधी समस्याओं का दीर्घकालिक पूर्ण निदान

कोरबा. छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा है कि कोरबा तथा उसके आसपास के क्षेत्र में सड़कों पर लगातार कार्य किया जा रहा है तथा अधिकांश सड़कों पर कार्य पूरा भी कर लिया गया है। उन्होने कहा कि कोरबा निगम क्षेत्र में बीते 06-07 वर्षो में जिस तरह से पानी व बिजली संबंधी समस्याओं का पूर्ण एवं दीर्घकालीन निराकरण कर लिया गया है, ठीक उसी तरह यहाँ की सड़क संबंधी समस्याओं का भी दीर्घकालिक एवं पूर्ण निदान शीघ्र ही कर लिया जाएगा। उक्त बातें राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल ने बालको नगर में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान कही। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा वार्ड क्र. 41 अंतर्गत 15 लाख रूपये की लागत से सड़क डामरीकरण का कार्य कराया जाना हैं। इसी प्रकार वार्ड क्र. 39 इंदिरानगर में 08 लाख 70 हजार रूपये की लागत से सड़क डामरीकरण का कार्य होना है। बालकोनगर स्थित परसाभांठा कांजीहाउस के पास आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करते हुए उक्त दोनों कार्यो का भूमिपूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर राजकिशोर प्रसाद के द्वारा की गई, वहीं विशिष्टि अतिथि के रूप में सभापति श्यामसुंदर सोनी, मेयर इन काउंसिल के सदस्य, पार्षद व एल्डरमेनगण उपस्थित थे। कार्यक्रम में दिए गए अपने उद्बोधन में राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि कोरबा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है, सार्वजनिक प्रतिष्ठान में भी उसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, बालको प्रबंधन के द्वारा भी सड़कों के निर्माण में सहयोग दिया जा रहा है, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

ज्ञानवापी के बाद मथुरा ईदगाह का कोर्ट कमिश्नर से सर्वे की मांग, कोर्ट ने स्वीकारी याचिका

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इलाहाबाद हाई कोर्ट में वादी मनीष यादव ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर के जरिए सर्वे कराने की मांग की है. मथुरा कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और अब मामले की सुनवाई 1 जुलाई को होगी. दरअसल, प्रार्थी मनीष यादव, महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा ने अलग-अलग एक ही तरह की याचिका लगाई थी, जिसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी कराई जाने की मांग की गई थी. इस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और सभी वादियों को एक ही तारीख यानी 1 जुलाई दे दी गई है. याचिकाकर्ता मनीष यादव के वकील देवकीनंदन शर्मा का कहना है, ईदगाह के अंदर जो शिलालेख हैं, उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा हटाया जा सकता है और एविडेंस को नष्ट किया जा सकता है, दोनों पक्षकारों की मौजूदगी में वहां की फोटोग्राफी कराई जाए और सभी तथ्यों को जुटाया जाए. इस मामले में अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी. इस मामले में एक और वादी महेंद्र सिंह का कहना है, %उन्होंने सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मस्जिद मामले में 24 फरवरी 2021 को एक प्रार्थना पत्र दिया था.

अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा महापौर और अध्यक्ष का चुनाव

भोपाल। मप्र में इस बार महापौर और नगर पालिका तथा नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। इनका जनता के माध्यम से नहीं कराया जाएगा बल्कि मतदाता पार्षद चुनेंगे और पार्षदों में से महापौर और अध्यक्ष का चुनाव होगा। मालूम हो कि पिछली कमल नाथ सरकार के समय बनाई गई यह व्यवस्था आज भी प्रभावी है। शिवराज सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से पुरानी व्यवस्था बहाल तो कर दी थी लेकिन विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया था। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा व्यवस्था में नगर निगम के महापौर और नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही होगा।

रायपुर में लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ सरकारी हेलिकॉप्टर

रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर गुरुवार रात सरकारी हेलिकॉप्टर अगस्ता वैस्टलैंड क्रैश हो गया। चॉपर में मौजूद दोनों पायलट्स की मौत हो गई है। ष्टरू भूपेश बघेल ने घटना पर दुख जताया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, टेक्निकल फॉल्ट के कारण यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान चॉपर तेजी से जमीन से टकराया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। रेस्क्यू टीम और पुलिस मौके पर मौजूद हैं। देर रात तक हेलिकॉप्टर का मलबा हटाने का काम शुरू था। एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा कि इस दुर्घटना के कारण रूटीन फ्लाइट पर कोई असर नहीं रहेगा। सभी उड़ानें सामान्य रहेंगी। रायपुर के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने कहा- प्रदेश सरकार का हेलिकॉप्टर क्रैश हुआ है। रायपुर के एयरपोर्ट पर रात 9 बजकर 10 मिनट पर यह हादसा हुआ। चॉपर के दो पायलट कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा और कैप्टन एपी श्रीवास्तव फ्लाइंग प्रैक्टिस कर रहे

थे। इसी वक्त अचानक ये हादसा हुआ। क्रैश में दोनों पायलट की मौत हो गई। कैप्टन पांडा ओडिशा के रहने वाले हैं। पिछले कुछ सालों से वे प्रदेश सरकार में सीनियर पायलट का काम कर रहे थे। कैप्टन श्रीवास्तव दिल्ली के रहने वाले थे। दोनों को रेस्क्यू टीम ने किसी तरह मलबे से बाहर निकाला। इन्हें तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो चुके दोनों कैप्टन को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस, प्रशासन के उच्चाधिकारी एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर दुर्घटना के कारणों की जानकारी लेते रहे।

मुख्यमंत्री ने दुख जताया

अभी रायपुर में एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की दुखद सूचना मिली। इस दुखद हादसे में हमारे दोनों पायलट कैप्टन पंडा और कैप्टन श्रीवास्तव का दुखद निधन हो गया है। इस दुःख की घड़ी में ईश्वर उनके परिवारजनों को संबल एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। शांति छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने हादसे पर दुख जताते हुए अपने ट्वीट में लिखा- रायपुर में हुए स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश में दोनों पायलट के निधन के दुःखद समाचार से मन बहुत आहत और अशांत है।

कलेक्टर ने जनसमस्या निवारण शिविरों का किया निरीक्षण

आबादी पट्टा के मिले सबसे ज्यादा आवेदन, राशन कार्ड का तुरंत ऑनलाइन किया निराकरण

भिलाई। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने भिलाई तहसील कार्यालय सहित जोन 3 के वार्ड 31 मदर टेरेसा नगर में गुरूद्वारा के पीछे सामुदायिक भवन और जोन 4 के चंद्रशेखर आजाद नगर वार्ड 39 के सुभाष नगर सामुदायिक भवन में लगे जनसमस्या निवारण शिविर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, जोन 3 आयुक्त येशा लहरे, जोन 4 आयुक्त अमिताभ शर्मा, जोन स्वास्थ्य प्रभारी द्वय महेश पांडे व सुदामा परगनिहा मौजूद थे। इस दौरान कलेक्टर डॉ. भुरे ने तहसील कार्यालय का भी निरीक्षण किया और सीमांकन, राजस्व मामलों से संबंधित व पेंडिग कार्य के जल्द निपटान करने के निर्देश तहसीलदार क्षमा को दिए। जनसमस्या निवारण शिविरों में शिकायतों के निराकरण के लिए दिए गए आवेदनों का अवलोकन किया। उन्होंने निगम आयुक्त व जोन के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का शीघ्रता से निराकरण कराया जाए.

न्यूज ब्रीफ

अपूर्ण भवनों को शीघ्र पूर्ण करायें : लोक निर्माण मंत्री श्री भार्गव

भोपाल। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने विंध्याचल और सतपुड़ा भवनों के संधारण तथा 5 महानगरों की सड़कों के वर्षा पूर्व संधारण के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश विभागीय समीक्षा बैठक में दिये हैं। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों से गुजरने वाली लोक निर्माण विभाग की सड़कों तथा राजमार्गों की रिपेयरिंग तुरंत प्रारंभ की जाये। उन्होंने प्रदेश में अपूर्ण बड़ी परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश भी दिये। प्रमुख सचिव श्री नीरज मण्डलोई सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री श्री भार्गव ने 491 करोड़ रूपये की लागत से छिंदवाड़ा में बनाये जा रहे मेडिकल कॉलेज भवन, 319 करोड़ रूपये की लागत से इंदौर में बनाये जाने वाले जिला सत्र न्यायालय के 10 मंजिला भवन, ग्वालियर में 338 करोड़ रूपये की लागत से बनाये जा रहे 100 बिस्तरीय अस्पताल भवन के निर्माण में देरी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति या मंत्रि-परिषद से अतिरिक्त स्वीकृति या अनुमति की आवश्यकता है, तो प्रस्ताव तुरंत तैयार किये जायें। मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि भोपाल शहर के प्रमुख कार्य, जो सीपीए से विभाग को हस्तांतरित किये गये हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने कहा कि सीपीए की जिम्मेदारी विभाग के वृहद दृष्टिकोण और अरबन प्लानिंग में निपुण अधिकारी को ही दी जाये। उन्होंने कहा कि राजधानी परियोजना से हस्तांतरित भोपाल के सभी महत्वपूर्ण भवन, विधानसभा, वल्लभ भवन, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन और शौर्य स्मारक का रख-रखाव महत्वपूर्ण कार्य है। इसी कड़ी में उन्होंने सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के संधारण का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये।

वर्षा पूर्व हो सड़कों का संधारण

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि वर्षा से पहले आरडीसी, पीडब्ल्यूडी और राष्ट्रीय राजमार्ग अपनी सभी सड़कों का संधारण कार्य पूर्ण कराये। इसी कड़ी में सभी लोक निर्माण संभाग को पर्याप्त मात्रा में इमलशन की उपलब्धता के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भोपाल शहर में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई 450 किलोमीटर सड़क तथा सीपीए से स्थानांतरित होकर आई 92 किलोमीटर सड़कों का प्राथमिकता से स्थल निरीक्षण कराया जाये।

एक डॉक्टर के नाम पर नहीं खुलेंगे दो निजी अस्पताल

रेजिडेंट डॉक्टर का दो नर्सिंग होम के बोर्ड पर भी नाम नहीं लिख पाएंगे संचालक

भोपाल

कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन और दवाओं का संकट बढ़ा तो मुनाफे के चक्कर में सैकडों नए अस्पताल खुल गए थे। इन अस्पतालों में एक ही डॉक्टर के नाम को कई अस्पतालों ने लिखवा कर स्वास्थ्य विभाग में पंजीयन भी करा लिया था। प्रायवेट अस्पतालों के इस फर्जीवाड़े पर अब स्वास्थ्य महकमे ने सख्ती दिखाई है। अब रेजिडेंट डॉक्टर के नाम से पंजीकृत अस्पताल के अलावा दूसरे नर्सिंग होम उस डॉक्टर का नाम अपने बोर्ड पर नहीं लिखवा सकेंगे। हालांकि रेजिडेंट के तौर पर पंजीकृत डॉक्टर बतौर कंसल्टेंट अधिकतम तीन अस्पतालों में जाकर इलाज और सर्जरी कर सकेंगे।

एक डॉक्टर का नाम पर खुले हैं कई अस्पताल:- भोपाल सहित प्रदेश भर में कई ऐसे निजी अस्पताल खुले हैं जिनमें एक ही चिकित्सक को रेजिडेंट डॉक्टर बताकर कई प्रायवेट अस्पताल पंजीयन करा लेते हैं। कोरोना संकटकाल में नियम कायदों का ताक पर रखकर खुले प्रायवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम के

फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है।

कोरोना संकट के दो साल में भोपाल में खुले सौ से ज्यादा नए अस्पताल:- स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संकटकाल में भोपाल में सौ से ज्यादा नए प्रायवेट अस्पताल खुले हैं। सीएमएचओ ऑफिस में कराए गए रजिस्ट्रेशन के अनुसार साल 2020 में भोपाल जिले में 30 नए नर्सिंग होम रजिस्टर्ड हुए। साल 2021 में 75 एलोपैथिक और 5 निजी आयुर्वेदिक अस्पताल खुले हैं। इस साल के शुरूआती चार महीने में 20 नए नर्सिंग होम रजिस्टर्ड हुए हैं।

अब ये नियम होगा लागू:- स्वास्थ्य विभाग ने मप्र उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम 1997 में संशोधन किया है। अब रेजिडेंट रेगुलर मेडिकल प्रेक्टिशनर (आवासी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी) के तौर पर एक डॉक्टर सिर्फ एक ही नर्सिंग होम में रजिस्टर्ड हो सकेगा। बतौर कंसल्टेंट डॉक्टर उसे अधिकतम तीन अस्पतालों में जाने की छूट रहेगी। लेकिन कंसल्टेंट्स के तौर पर निजी अस्पताल उसका नाम अपने बोर्ड या अस्पताल में नहीं लिखवा पाएंगे।

पोर्टल पर एक बार नाम रजिस्टर्ड होते ही नहीं हो पा रही एंट्री:- स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बताते हैं कि इस व्यवस्था के तत्काल बाद नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर भी बदलाव कर दिए गए हैं। अब एक बार किसी अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर पोर्टल में एंट्री होने के बाद डॉक्टर का नाम दोबारा दर्ज नहीं रहा है।

हेल्थ कमिश्नर बोले- लोगों को सही जानकारी और अच्छा इलाज मिले

स्वास्थ्य आयुक्त डॉ.सुदाम खाड़े का कहना है कि कई बार ऐसी शिकायतें मिलतीं रहीं हैं कि एक डॉक्टर के नाम से कई नर्सिंग होम और प्रायवेट अस्पताल चल रहे हैं। जबकि वास्तविकता में वह डॉक्टर वहां कई बार उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में मरीजों को समय पर विशेषज्ञ चिकित्सक से इलाज नहीं मिल पाता। अब रेजिडेंट डॉक्टर्स के नाम का उपयोग एक से ज्यादा अस्पताल में नहीं किया जा सकेगा। हमारी कोशिश है कि लोगों को सही जानकारी और अच्छा उपचार मिले।

नगरीय निकायों के चुनाव ईव्हीएम और पंचायतों के मतपत्र से होंगे

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने की चुनाव तैयारियों की समीक्षा

भोपाल

नगरीय निकायों के चुनाव में ईव्हीएम और त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनाव में मतपत्र और मतपेटियों का उपयोग किया जाएगा। पंचायतों का चुनाव भी ईव्हीएम से करवाने पर 3 माह से अधिक समय लगेगा, क्योंकि ईव्हीएम की संख्या सीमित है। इसलिए मतपेटियों के माध्यम से पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने यह बात कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा के दौरान कही। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों के चुनाव 2 चरण में और पंचायतों के चुनाव 3 चरण में करवाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों चुनाव साथ में कराना है, इसलिए ऐसी तैयारी करें कि किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। श्री सिंह ने कहा कि कोई भी समस्या हो, तो मुझे अथवा सचिव राज्य निर्वाचन आयोग को तुरंत बताएँ। उन्होंने कहा कि संवेदनशील और अति-संवेदनशील मतदान केन्द्रों की समीक्षा कर जानकारी जल्द आयोग को उपलब्ध कराएँ। निर्वाचन प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग करें। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिये चुनाव मोबाइल एप का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। श्री सिंह ने कहा कि नवीन प्रावधानों के अनुरूप पार्षदों के निर्वाचन व्यय के लेखा का संधारण व्यवस्थित रूप से करवाएँ। उन्होंने कहा कि रिजर्व ईव्हीएम सुरक्षित तरीके से निर्धारित स्थानों पर ही रखवाएँ।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण का दीप जला कर शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार परिसर में किया पौध-रोपण

भोपाल

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार परिसर में राष्ट्रीय महामंत्री श्री बी.एल. संतोष के साथ नीम और पीपल के पौधे लगाए। देश के पहले ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण में भाग लेने आए जनजातीय कलाकार भी पौध-रोपण में शामिल हुए। आज लगाया गया पीपल एक छायादार वृक्ष है। यह पर्यावरण शुद्ध करता है। इसका धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व है। एंटीबायोटिक तत्वों से भरपूर नीम को सर्वोच्च औषधि के रूप में जाना जाता है।

प्रदेश में तेज गति से जारी है अमृत सरोवरों का निर्माण

» 5638 चयनित, 5449 का कार्य प्रारंभ

भोपाल

आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन में प्रदेश में अमृत सरोवर के निर्माण का कार्य तेज गति से चल रहा है। प्रत्येक जिले में कम से कम 100 अमृत सरोवर बनाये जायेंगे। अभी तक प्रदेश में 5 हजार 638 अमृत सरोवर के लिये स्थल चयन किया गया है, जिनमें 5 हजार 449 पर निर्माण कार्य जारी है। इनमें 29 अमृत सरोवरों के निर्माण का कार्य 75 प्रतिशत से अधिक, 134 का 50

प्रतिशत से अधिक, 1204 का 25 प्रतिशत से अधिक एवं 4 हजार 82 अमृत सरोवरों का 25 प्रतिशत तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ये सभी अमृत सरोवर वृहद स्वरूप में और गुणवत्तापूर्ण बनाये जा रहे हैं। इनका उपयोग सिंचाई, मत्स्य-पालन, सिंघाड़ा उत्पादन आदि प्रयोजन में किया जायेगा। न्यूनतम भण्डारण क्षमता 10 हजार घन मीटर होगी। ये महात्मा गाँधी नरेगा एवं अन्य शासकीय योजनाओं के अभिसरण से बनाये जा रहे हैं। लाभार्थी ग्रामीणों के जल उपयोगकर्ता समूहों का गठन भी किया गया है। अमृत सरोवर योजना में नयी जल-संरचनाओं के निर्माण के साथ स्थानीय लोगों को मनरेगा में रोजगार भी मिल रहा है। मुरैना जिले की ग्राम पंचायत खिरिका, जनपद पंचायत सबलगढ़ एवं मण्डला जिले के ग्राम बड़हर, जनपद पंचायत मण्डला में अमृत सरोवर के निर्माण में पिचिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत सांपखड़की एवं पिपरानी जनपद पंचायत पानसेमल, खण्डवा जिले के ग्राम मिरीखेड़ी और बालाघाट जिले के ग्राम टिगीपुर जनपद पंचायत बिरसा में बनाये जा रहे अमृत सरोवरों की पडल खुदाई का कार्य हो गया है। नरसिंहपुर जिले की ग्राम पंचायत बिलहेरा जनपंचायत चावरवाठा के अमृत सरोवर के निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

प्रदेश में टायर जलाने के नहीं लगेंगे नये प्लांट

भोपाल

पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि प्रदेश में टायर जलाने के नये प्लांट को अब अनुमति नहीं दी जायेगी। इससे प्रदूषण में रोकथाम होगी। अभी प्रदेश की जिन सीमेंट फेक्ट्री में उच्च तापमान के कारण प्रदूषण नगण्य है। वे इसे जारी रख सकते हैं। मंत्री श्री डंग ने यह बात आज पर्यावरण विभाग और मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कही। कार्यपालन संचालक एप्को श्री श्रीमन शुक्ला, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री ए. मिश्रा और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

शिवना नदी में नहीं मिलेगा सीवेज का पानी

मंत्री श्री डंग ने बताया कि मंदसौर जिले की शिवना नदी के पर्यावरण प्रबंधन के लिये केन्द्र शासन से प्रथम

किश्त के रूप में 30 करोड़ रूपये की स्वीकृति मिली है। अभी शहर के सीवेज का गंदा पानी शिवना में जाने से नदी प्रदूषित हो रही है। स्वीकृत राशि से 8 किलोमीटर का ड्रेन सिस्टम निर्मित कर सीवेज को शहर के बाहर ऑक्सीनेटेड तालाब में प्रवाहित किया जाएगा। वर्षा का सम्पूर्ण जल नदी में यथावत मिलता रहेगा।

पेड़ काटने के बदले कितने पेड़ लगाये, जानकारी लें

मंत्री श्री डंग ने कहा कि कई जगह पर अस्पताल, स्कूल या अन्य अति आवश्यक निर्माण होने से पेड़ों की कटाई होती है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि ऐसे स्थलों की जानकारी प्राप्त करें कि उन्होंने बदले में कहाँ पर और कितने पेड़ लगाये हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि उन पेड़-पौधों की देखभाल अच्छी तरह हो रही है या नहीं। मंत्री श्री डंग ने वेटलैंड, सिया, सियाक, ग्लोबल वॉर्मिंग, जलवायु संतुलन और अपशिष्ट प्रबंधन आदि अन्य विषयों पर किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली।

दैनिक इंटीग्रेटेड ट्रेड डेवलपमेंट सेंटर न्यूज
मध्य भारत का एक विश्वसनीय दैनिक | 98 26 22 00 22

अर्थव्यवस्था, शिक्षा,
नियोजन, उद्भव,
पर्यावरण, मनोरंजन.

आपकी बात
आपके साथ

हसदेव अरण्य में आदिवासियों के लगातार विरोध के बावजूद पेड़ काटे जा रहे, काम रोको आदेश हो नही तो उग्र आंदोलन होगा : कोमल हुपेंडी

आदिवासियों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी 21 मई को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी - प्रियंका शुक्ला

रायपुर। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में आदिवासी लगातार विरोध कर रहे है और पर्यावरण विशेषज्ञों की चेतावनी के बाद भी राज्य की कांग्रेस सरकार ने परसा कोयला खदान को मंजूरी दे दी है। यह कोयला खदान दूसरे कांग्रेसी राज्य राजस्थान को आवंटित किया गया है।

सरकार के कहने पर ही भारत सरकार की संस्था वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (ड्ढड्ढड्ढ)ने हसदेव अरण्य का अध्ययन कर पिछले साल ही रिपोर्ट सौंपी है। ड्ढड्ढड्ढ ने अपनी रिपोर्ट में साफ-साफ कहा था कि यहां एक भी कोयला खदान को मंजूरी देने के विनाशकारी परिणाम होंगे, जिसे रोक पाना असंभव होगा।

ड्ढड्ढड्ढ (वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया) की रिपोर्ट अनुसार *मध्यभारत का फेफड़ा* कहे जाने वाले हसदेव अरण्य के इलाके में नये खदान की मंजूरी से जंगल का विनाश तो होगा ही, जंगल में रहने वाले हाथी, बाघ, तेंदुआ, भालू जैसे जानवरों का भी जीवन खतरे में आ जाएगा। साथ ही हाथी मानव संघर्ष अत्याधिक बढ़ेगा।

ड्ढड्ढड्ढ की रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की मार झेल रहे मध्य भारत के सबसे घने जंगलों के विनाश से तापमान में और बढ़ोत्तरी होगी और पानी संकलन में कमी के चलते सूखा पड़ने की आशंका है।

हसदेव अरण्य के गांव में ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव से पूर्व कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार आई तो वे आदिवासियों के साथ खड़े रहेंगे और कोयला खदान नहीं खुलने देंगे,लेकिन सरकार बनने के बाद सब कुछ भूलकर खदानों को मंजूरी देना शुरु कर दिया गया है और इसी तरह के वादे अब राहुल गांधी दूसरे चुनावी राज्यो में भी कर रहे है।यह बेहद गलत है,और इससे सरकार की नीयत और वादा खिलाफी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे है।

कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी बार-बार अपने भाषणों में भाजपा की केंद्र सरकार को अडानी अंबानी की सरकार कहकर उल्लेख करते रहे हैं, लेकिन यह दिलचस्प है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही अपना कोयला खदान एमडीओ के आधार पर अडानी को सौंप दिया है। राजस्थान सरकार को जो परसा कोयला खदान सौंपा गया है, कांग्रेस पार्टी की राजस्थान सरकार ने इस परसा खदान को भी एमडीओ का अनुबंध कर के पूरी तरह अडानी कंपनी को सौंप दिया है।

आम आदमी पार्टी ने आज प्रदर्शन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी के नेतृत्व में आज अंबिकापुर में लोगो को संबोधित करते हुए प्रदर्शन किया। कोमल हुपेंडी ज्ञापन कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ का जनता व हसदेव के लोगो के संघर्ष में साथ देने का शंखनाद किया। कोमल हुपेंडी ने कहा कि सरकारें अडानी की गोद मे जाकर बैठ चुकी है लेकिन हम हसदेव अभ्यारण्य में खदानों के कोई काम नही होने देंगे चाहे हमें कुछ भी करना पड़े।

हम प्रदेश सरकार से मांग करते है कि

1-फर्जी ग्राम सभा की जांच करवाई जाए
2- ड्ढड्ढड्ढ की रिपोर्ट को संज्ञान में ले सरकार और तुरंत पेड़ कटाई बंद करवाया जाए।
3- पाँचवी अनुसूचित इलाके का नियम का पालन हो, ताकि फर्जी तरह से काम बंद हो।

आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों की टीम जब गाँव वालों के साथ मिलकर जंगलों में गई जहां पेड़ो को काटने का काम देर रात में किया गया है। वहाँ मौके पर हालात को देखा और पाया गया कि बड़े बड़े लगभग 300 पेड़ो को रातों रात काट दिया गया। ये पेड़ महुआ, साल के बड़े बड़े पेड़ थे, साथ ही तेंदू पत्ते के छोटे झाड़ को भी नुकसान हुआ।गाँव के आनंदराम ने बताया कि इन पेड़ों से लगभग 50,000 का महुआ हमने बेचा था और प्रतिदिन तेंदू पत्ता संकलन से 1000 की कमाई होती है और इसी काम पर हम आदिवासी लोगो की आजीविका निर्भर है,जिसका आदिवासियों को उसको बड़ा नुकसान पंहुचा है।

आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष कोमल हुपेंडी के नेतृत्व में, प्रदेश कोषाध्यक्ष जसबीर सिंह,सचिव संगठन विस्तार गोपाल साहू,प्रदेश यूथ विंग अध्यक्ष तेजेंद्र तोडकर,प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका शुक्ला, सह संगठन मंत्री अधिवक्ता दिव्य प्रकाश यादव,अम्बिकापुर के जिला संयोजक अधिवक्ता कुंज बिहारी पैकरा, राजदीप शर्मा, आज़म मिर्ज़ा, बिलासपुर के संतोष बंजारे, दिनेश अनंत, खगेश केवट आदि हसदेव के आंदोलन में अपना समर्थन देते हुए आम लोगो के साथ प्रदर्शन किया और आश्वस्त किया कि आम आदमी पार्टी सदैव हर स्थिति में लड़ने को तैयार है।

अंत में कोमल हुपेंडी ने कहा कि समस्त तथ्यों को संज्ञान में लेकर आदिवासियों की मांगो को पूरा किया जाना चाहिए। यदि सरकार मामले को गंभीरता से लेते हुए, हमारी मांगो को 20 मई 22 तक नही मानती है, तो आम आदमी पार्टी द्वारा 21/05/22 को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी।

आम जन में काफी आक्रोश है और उग्र आंदोलन वाली स्थिति बन रही है,यदि ऐसी स्थिति सरकार बनने देती है, तो इसकी समस्त जिम्मेदार कांग्रेस की प्रदेश में बघेल सरकार होगी।

विकास कार्यों का मेंटेनेंस तक नहीं कर पा रही सरकार डॉ- रमन सिंह

राजनंदगांव। पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह आज कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति विस्तारक योजना के तहत शक्ति केंद्र बेल्टिकरी एवं खैरा पहुंचे, जहां पर हजारों की की संख्या में ग्रामीण एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्राम खैरा में डॉ रमन सिंह ने कहा कि 15 वर्षों तक भाजपा के छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम काल कार्यकाल को आज भी जनता याद करती है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ में विकास के कीर्तिमान स्थापित हुए ।सड़क, पुल, पुलिया, सिंचाई के साधन , शादी योग्य बच्चियों का विवाह, बाल हृदय योजना के तहत 9000 बच्चों का निशुल्क ऑपरेशन, स्वास्थ्य लाभ, सिंचाई योजना, सिंचाई संसाधन ड्रिप इरिगेशन, बिजली पोल, प्रधानमंत्री आवास बनाना इत्यादि कार्यों के साथ-साथ एक रुपए चावल की योजना भाजपा ने ही बनाई ।

डॉ रमन सिंह ने कहा कि किसानों को बिना ब्याज के कर्जे का मूल मंत्र भाजपा शासनकाल में ही तय किया गया। इसके पूर्व कांग्रेस की सरकारों में किस तरह से लूट मचाई थी,ये सभी जानते हैं। डॉ रमन सिंह ने कहा कि लबारी मार के भूपेश बघेल सरकार में आए हैं, उनकी घोषणा पत्र में किए गए वायदों आज भी अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी की बात करने वाले भूपेश घर घर पहुंचा कर शराब बांट रहे हैं ।कोविड काल के समय में दवाई पहुंचाने की मानवता छोड़कर घर-घर दारू पहुंचाने की योजना भूपेश ने लाई।

डॉ रमन सिंह ने कहा कि 25 सौ रुपए धान खरीदी करने की बात करने वाले बघेल सरकार ने किसानों को एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से लिया ही है, एक और जहां किसानों का रकबा कट गया, वही बोरा उपलब्ध नहीं कराया गया और 4 किस्त में पैसा देकर आखिरी किस्त में 290 करोड़ों रुपए की कटौती की गई,जो कि किसानों के साथ सरासर अन्याय है। डॉ रमन सिंह ने कहा कि तेडसरा एवं कई ऐसे गोठान उन्होंने देखे हैं, जहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं परंतु एक गाय भी उपलब्ध नहीं है और वर्मी कंपोस्ट खाद,जो की पैरा भूसा और मिट्टी मिलाकर बनाई जा रही है वह 900 में अनिवार्य रूप से किसानों को दी जा रही है । डॉ रमन सिंह ने केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं को विस्तार से बताते हुए कहा कि आगामी 2024 में भी जनता ने यह तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी को वापस लाकर पूरे विश्व में देश को सशक्त बनाना है डॉ रमन सिंह ने बेल्टिकरी ग्राम के शक्ति केंद्र में 8 बूथों के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और बताया कि वर्तमान सरकार जो 15 वर्षों में भाजपा ने विकास कार्य किए थे उसका मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रही है। विकास कार्यों के लिए जो बड़ी-बड़ी योजनाएं लागू की गई। बिल्डिंग बनाई गई, उसकी पुताई तक करने में अक्षम सरकार अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर चुकी है।

शिक्षा विभाग के नए सेटअप मे संस्कृत को दर्ज संख्या के प्रतिबंध से मुक्त करने नवीन शिक्षक संघ ने सौपा मांग पत्र

कान्हा तिवारी, जांजगीर चांपा. नवीन शिक्षक संघ के जिला पदाधिकारियो ने शिक्षा विभाग व्दारा जारी नवीन सेटअप मे संस्कृत विषय को दर्ज संख्या के प्रतिबंध से मुक्त करने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव इँजी रवि पाण्डे को मांग पत्र सौप कर संस्कृत विषय को माध्यमिक सहित हाई व हायर सेकण्ड्री मे अनिवार्य विषय के रूप मे सम्मिलित करने की मांग जिला पदाधिकारियो के व्दारा किया गया जिस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव इँजी रवि पाण्डेय ने त्वरित संग्यान लेते हुए मुख्यमंत्री सहित प्रभारी मंत्री को पत्र लिखने की बात कही इस संबंध मे विस्तृत जानकारी देते हुए नवीन शिक्षक संघ के

जिलाध्यक्ष अनुभव तिवारी रफीक अली राघवेन्द्र शर्मा रामस्वरूप साहू ने बताया की शासन स्तर पर हाल ही मे नवीन सेटअप का आदेश जारी हुआ है जिसमे संस्कृत विषय को लेकर दर्ज संख्या के आधार पर संस्कृत विषय के शिक्षक रखने का उल्लेख है चूंकि संस्कृत हमारी देव वाणी है व सर्वाधिक प्राचीन भाषा है साथ ही माध्यमिक स्तर से लेकर हाई हायर तक के छात्रो को संस्कृत विषय की पढाई करने की आवश्यकता होती है जो बिना विषय शिक्षक के संभव नही है इस संबंध मे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव इँजी रवि पाण्डेय ने गंभीरता से संगठन की बातो को सुना व त्वरित प्रयास करने का आश्वासन दिया है.

वन विभाग से बस्तर में 32 लाख वनवासियों को मिला रोजगार

जगदलपुर। बस्तर संभाग में वन मंडलों ने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वृहन रूपरेखा तैयार की गई तथा बाहरी राज्यों से वापस आए सैनिकों के साथ- साथ स्थानीय निवासियों से मिलकर पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था वन विभाग द्वारा की गई। वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी द्वारा जिससे मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य कैंपा मद के कार्य नवा नाला संरक्षण तथा भू-जल संरक्षण एवं वन्य प्राणियों के लिए अनेक कार्य कराए गए। वनों की सुरक्षा के लिए भी अनेक कदम उठाए गए। बस्तर संभाग में 800 करोड़ का रोजगार सृजनकर 32 लाख वनवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। और वानिकी कार्य में कार्य करने वाले भविष्य में भी दूसरे रोजगार के लिए दूसरे प्रांत जाना न पड़ेगा।

वनमण्डलाधिकारी द्वारा मुंगेली एवं पथरिया के रोड साइड प्लांटेशन का निरीक्षण

हरजीत कुमार, मुंगेली

वनमण्डलाधिकारी गणेश यू आर द्वारा मुंगेली एवम पथरिया परिक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर रोड किनारे हुए वृक्षारोपण का निरीक्षण किया गया। जिसमे कुछ स्थानों पर किए गए कार्य संतोषजनक नहीं होने के कारण संबंधित रोपनी प्रभारी को फटकार लगाते हुए, तुरंत सुधार हेतु निर्देश दिए गए। साथ ही परिक्षेत्र अधिकारी के माध्यम से कारण बताओ नोटिस भी दिया गया। वनमण्डलाधिकारी द्वारा इस हेतु कई दिशा निर्देश दिए गए। जिसमे टूटे हुए ट्री गार्ड के

मरम्मत करना, ट्री गार्ड/पौधो को असामाजिक तत्वों द्वारा हानि पहुंचाने पर संबंधित पर कार्यवाही करने, प्रजाति ऐसे चयनित करें कि बंदर मावेशी द्वारा नुकसान ना पहुंच पाए एवं जिससे गर्मी के मौसम में भी जन सुविधा सुनिश्चित हो, प्राक्कलन अनुरूप सिंचाई उचित समय पर करने, साथ ही साथ स्वीकृत परियोजना के आधार पर बरसात के मौसम में कैजुअल्टी रिप्लेसमेंट करने हेतु उच्च गुणवत्ता के पौधे की तैयारी हेतु दिशा निर्देश दिया गया एवं रोपनी में पौधा तैयारी के समीक्षा लिया गया। मुंगेली जिले में बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए रोड साइड वृक्षारोपण जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं के संचालन में उदासीनता नहीं बरतने हेतु स्पष्ट चेतावनी परिक्षेत्र अधिकारी सहित संबंधित मैदानी अमले को दिया गया। इस निरीक्षण के दौरान उपवन मंडल अधिकारी मानवेंद्र कुमार के साथ मुंगेली पथरिया रेंज के मैदानी अमले उपस्थित रहे।

घुर नक्सल प्रभावित ग्राम में पहली बार पंहुचाजिला प्रशासन

जनचौपाल समाधान शिविर में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, दी कई सौगातें

जगदलपुर। बस्तर जिले के कांगेर घाटी के गोद में बसे दरभा विकासखण्ड के अतिसंवेदनशील और दुर्गम गांव चांदामेटा में जन चौपाल समाधान शिविर का आयोजन किया गया है। जहां कलेक्टर रजत बंसल, पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र मीणा, कांगेर घाटी राष्टीय उद्यान के संचालक धम्मशील गणवीर सहित आला अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और ग्रामीणों की मांग पर कई सौगातें भी दीं। पहली बार जिला प्रशासन को देखकर ग्रामीणों में खासा उत्साह दिखा, वहीं कलेक्टर सहित अधिकारियों के आत्मीय और मधुर व्यवहार से ग्रामीणों में अत्यंत प्रसन्नता दिखी। चांदामेटा के ग्रामीणों की मांग के अनुसार बस्तर कलेक्टर ने तत्काल आंगनबाड़ी केंद्र ,स्वास्थ्य सुविधा संचालन करने सम्बंधित अधिकारी को निर्देश दिये। राशन कार्ड व राशन वितरण हेतु भवन, वृद्धा पेंशन हेतु आवेदन तैयार करने, राशन कार्ड दिलाने पंचायत सचिव को निर्देश दिया। चांदामेटा के पटेलपारा में देवगुड़ी निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की। ग्रामीणों की मांग पर चांदामेटा में शीघ्र ही मोबाइल टावर लगाने की बात भी अधिकारियों ने कही। चांदामेटा गांव में जन चैपाल समाधान शिविर के आयोजन से शासन के आला अधिकारी चांदामेटा पहुंचे जहां ग्रामीण आला अधिकारी के उपस्थिति को देख खुश नजर आये क्योंकि आजादी के पश्चात पहली बार यहां शिविर लगा और बस्तर कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारी चांदामेटा पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, क्रेडा विभाग, विद्युत विभाग, पशु चिकित्सा विभाग सहित सभी विभागीय अधिकारियों ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुना। यहां इस दौरान ग्रामीणों ऋ ण पुस्तिका, राशन कार्ड, बीज, फलदार पौधों का वितरण किया गया। बस्तर रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने ग्रामीणों को हाईजिन किट और मच्छरदानी का वितरण भी किया। उल्लेखनिय है कि चांदामेटा और चांदामेटा की पहाडियां, नक्सलियों की सुरक्षित पनाहगाह मानी जाती रही है। कभी अगर यहां जवान पहुंच भी जाते तो नक्सली पहाड़ पार कर ओडिशा की ओर भाग निकलते थे, यह पूरा इलाका दरभा, कटेकलायण इलाके में वारदात के बाद ओडिशा जाने के लिए नक्सलियों के क्रॉसिंग प्वाइंट के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन अब इस पहाड़ी पर जवानों का कब्जा है। इस गांव से दरभा डिवीजन के तीन बड़े नक्सली पांडू, कुट्टे, हिड़में जैसे बड़े नक्सलियों का प्रभाव एवं कब्जा था। ज्ञात हो कि कुछ समय पहले ही यहां एसपी जीतेंद्र मीणा के प्रयासों से पुलिस कैंप खोल दिया गया है। ग्राम चांदामेटा के पटेलपारा में रहने वाले 99 प्रतिशत परिवार का कोई न कोई सदस्य नक्सली मामले में जेल में है.

बीजापुर क्षेत्र का विकास मेरी पहली प्राथमिकता

बीजापुर। क्षेत्रीय विधायक एवं बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम शाह मंडावी को राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत नैमेड से दो किलो मीटर दूर बसे कुरसम पारा की रहने वाली सरिता कुरसम ने पिछले फरवरी माह में मोबाइल फ़ोन पर कुरसम पारा की सड़क को ग्राम नैमेड से जोडने की गुहार लगाते हुए कहा था कि कुरसम पारा में रहने वाले लोगों को बरसात के दिनों में सड़क नहीं होने से आने-जाने में भारी समस्याओं का सामना करना पढ़ता है, सड़क नहीं होने से आपातकालीन सेवाएँ भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है इसलिए इस सड़क का निर्माण बारिश के पहले किसी तरह बनाया जाए। सरिता की माँग को गम्भीरता से लेते हुए विधायक विक्रम शाह मंडावी ने सरिता से वादा किया था कि तीन माह के अंदर नैमेड से कुरसम पारा तक सड़क का निर्माण कर दिया जायेगा.

रद्द ट्रेनों को बहाल करने की मांग, स्टेशन के सामने प्रदर्शन

प्रशासन के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी

बिलासपुर । चालिस से अधिक यात्री गाडियों का परिचालन बन्द होने के बाद आम जनता का आक्रोश दिनो दिन बढ़ता जा रहा है। जनता के समर्थन में कांग्रेस ने भी आंदोलन तेज कर दिया है। इसी क्रम में गुरूवार को स्थानीय लोगों के साथ कोटा रेलवे स्टेशन के सामने कांग्रेस नेताओं ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण की अगुवाई में उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता संतोष कौशिक, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष आदित्य अवस्थी समेत अन्य कांग्रेसियों ने रेल प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण ने सीधे सीधे कोयलागाड़ी की पहियों पर ब्रेक लगाने का एलान भी कर दिया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी ने उपस्थित तीन सौ अधिक लोगों को संबोधित किया। उन्होने कहा कि कि जो काम ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने नही किया। उस जनविरोधी काम को गरीब विरोधी केन्द्र की भाजपा सरकार ने कर दिखाया है। कोटा रेलवे स्टेशन समेत छत्तीसगढ़ के सैकड़ों महत्वपूर्ण ट्रेन स्टापेज को रेल प्रशासन ने बन्द कर दिया। बिलासपुर से सभी दिशाओं में चलने वाली चालिस यात्री गाडियों के पहियों पर रेल मंत्रालय ने ब्रेक लगा दिया है।

रेल प्रशासन के तुगलकी फैसले से जनता में हाहाकार है। लेकिन केन्द्र सरकार बिजली संकट का अफवाह फैलाकर अडानी और अम्बानी के लिए धकापेल कोयला गाडियों को चला रही है। विजय केशरवानी ने बताया कि यात्री गाडियों के बन्द होने से सबसे बुरा प्रभाव स्थानीय व्यापार पर पड़ा है। गरीबों का तो जीना मुश्किल हो गया है। रात्रि में लगने वाली बेलगहना सब्जी मण्डी बन्द हो गयी है। इससे ना केवल गरीब किसानों और आदिवासियों को नुकसान हुआ है। बल्कि बेलगहना से प्रदेश और प्रदेश बाहर जानी वाली गरीब किसानों की सब्जियां कौड़ी के मोल हो गयी है। कोटा जैसे आदिवासी क्षेदत्र में यदि कोई गरीब बीमार हो जाए ..तो बिलासपुर पहुंचने में उसे 50 रूपयों की जगह पांच हजार रूपये खर्च करना पड़ता है। इस तुगलकी फरमान के खिलाफ प्रत्येक स्टेशन पर आंदोलन किया जा रहा है।

16 मई को भाजपा का जेल भरो आंदोलन

-डरी हुई सरकार अपने विरुद्ध होने वाले आंदोलन को कुचलने के लिए कुप्रयास कर रही है : बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर। कांग्रेस सरकार द्वारा जन आंदोलन को कुचलने के लिए लाए गए काले कानून के विरोध में भारतीय जनता पार्टी 16 मार्च को मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर, जेल भरो आंदोलन करने जा रही है। इसकी तैयारियों के लिए आज भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में बैठक आहूत की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के आपातकाल को देश की जनता ने टिकने नहीं दिया। उसके सामने कांग्रेस शासन के इस काले कानून की हैसियत ही क्या है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि देश में आंदोलन करने के लिए क्या अनुमति लेने की जरूरत पड़ेगी? लगता है उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काला कानून नहीं पढ़ा है। राहुल गांधी भाजपा को बदनाम करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस शासित राज्य में प्रदर्शन के लिए अनुमति लेने वाला काला कानून खुद ही लागू किए हुए है। उन्होंने कहा कि यह डरी हुई सरकार है जो अपने विरुद्ध होने वाले किसी भी आंदोलन को कुचलने के लिए विभिन्न कुप्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पूरे प्रदेश में भय का वातावरण बनाकर लोगों के मौलिक अधिकार छीनने का प्रयत्न कर रही है। उन्होंने कहा है कि 16 तारीख को इस अत्याचारी, दमनकारी, लोकतंत्र विरोधी सरकार के विरुद्ध विद्रोह का शंखनाद करना है। भाजपा जिला प्रभारी व प्रदेश उपाध्यक्ष खूबचंद पारख ने कहा कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का ब्रह्मास्त्र है। उन्होंने कहा कि अत्याचारी सरकार के दमन से जनता को मुक्ति दिलाने के लिए उस ब्रह्मास्त्र के संधान का वक्त आ गया है।

भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि कांग्रेस के 3 वर्षों में जनता को वादाखिलाफी, झूठ, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं मिला। अब जनता पूछ रही है कि जो वादे करके कांग्रेस सत्ता में आई थी वह कहां हवा हो गए। यह सरकार जनता की सवालों से डरकर काला कानून लेकर आई है। इसके विरोध में भाजपा 16 मई को रायपुर के चार स्थानों से मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर जेल भरो आंदोलन करेगी। बैठक का संचालन महामंत्री ओंकार बैस व आभार उपाध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा ने किया।

बैठक में मुख्यरूप से पूर्व ग्रामीण विधायक नंदे साहू, संजय श्रीवास्तव, देवजी भाई पटेल, राजीव अग्रवाल, मीनल चैबे, केदार गुप्ता, ओंकार बैस, अशोक पांडे, प्रफुल्ल विश्वकर्मा, डॉक्टर सलीम राज, सीमा साहू, जिला मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल, अमरजीत छाबड़ा, आशु चंद्रवंशी, बजरंग खंडेलवाल, अवधेश जैन, किशोर महानंद, मृत्युंजय दुबे, अनिल सोनकर, राहुल राव, खेम सेन, प्रीतम ठाकुर, श्रीनिवास राव, भूपेन्द्र ठाकुर, सुनील चैधरी, गोविंदा गुप्ता,बिट्टू शर्मा,गज्जू साहू, अनूप खेलकर,ओमप्रकाश साहू, रचना शुक्ला, रविन्द्र सिंह, मंजुल श्रीवास्तव उपस्थित थे।

संपादकीय

श्रीलंका में हालात बेकाबू

भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में सोमवार को हालात संभालने की गरज से प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इससे स्थितियां संभालने में खास मदद मिलेगी। उनके इस्तीफा देने से पहले ही वहां विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुके थे। सोमवार को कोलंबो और अन्य शहरों में हुई हिंसा में सत्तारूढ़ दल के एक सांसद सहित पांच लोगों के मारे जाने और 200 से अधिक के घायल होने की खबर थी। प्रदर्शनकारी जगह-जगह सत्तारूढ़ दल से जुड़े नेताओं के घरों को निशाना बना रहे हैं। पिछले करीब 20 वर्षों से श्रीलंकाई राजनीति में अपना दबदबा बनाए रखने वाले राजपक्षे परिवार के खिलाफ लोगों का गुस्सा आसमान छू रहा है। अभी भी जब प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे इस्तीफा दे चुके हैं, राष्ट्रपति पद पर उनके छोटे भाई गोटबाया राजपक्षे ही विराजमान हैं और प्रदर्शनकारी उनके भी इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। इसमें दो राय नहीं कि मौजूदा आर्थिक संकट के लिए सिर्फ राजपक्षे सरकार और उसकी नीतियां ही जिम्मेदार नहीं हैं। बेशक उसकी नीतियों ने इस संकट की पृष्ठभूमि तैयार की, लेकिन हालात को बेकाबू बनाने में कोरोना महामारी और यूक्रेन युद्ध जैसे कारकों की अहम भूमिका रही, जिस पर श्रीलंका सरकार का कोई वश नहीं था। लेकिन पिछले करीब डेढ़ महीने यानी अप्रैल की शुरुआत से आर्थिक संकट नए फेज में चला गया, जब श्रीलंका के आम लोगों का धैर्य जवाब दे गया और ईंधन के बेतहाशा बढ़ते दाम, बिजली कटौती और जरूरी वस्तुओं की किल्लत से परेशान लोग सड़कों पर निकल आए। हिंसक प्रदर्शन में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई और 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस अवस्था में भी राजपक्षे सरकार जनभावनाओं का आकलन करने में नाकाम रही। चाहे कैबिनेट से इस्तीफा दिलाने का सवाल हो या खुद प्रधानमंत्री के पद छोड़ने का, हर फैसला इतनी देर से देर से लिया गया कि उसका कोई सकारात्मक असर होने की संभावना खत्म हो गई। सोमवार की ही बात करें तो सुबह सरकार समर्थकों की एक रैली हुई, जिसके बाद सरकार के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हथियारबंद समूहों ने हमले शुरू कर दिए। यानी सरकार समर्थकों का एक हिस्सा अब भी यह समझ रहा था कि डरा-धमका कर और मारपीट कर सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर काबू पा लिया जाएगा। इस प्रयास ने हालात और खराब कर दिए। आगे स्थितियां जो भी मोड़ लें, यह तो हो ही गया है कि कल तक राजपक्षे सरकार का इस्तीफा मांग रहे लोग अब महिंदा राजपक्षे की गिरफ्तारी की मांग करने लगे हैं। बहरहाल राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अभी भी राष्ट्रीय सरकार के गठन का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष सहयोग के लिए अभी भी तैयार नहीं है। दिवालियापन के कगार पर खड़े देश के लिए यह स्थिति और विकट हो जाती है। आईएमएफ से बेलआउट पैकेज को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन सड़कों पर आम लोगों का लगातार प्रदर्शन और राजनीतिक अस्थिरता की यह स्थिति वित्तीय संकट से निकलने की कोशिशों का आगे बढ़ना और मुश्किल बना रही है।

अस्थिरता की आग में श्रीलंका

(ब्रह्मदीप अलूने)

श्रीलंका का संकट नव उपनिवेशवाद की चुनौतियों को सामने लाने वाला है, जिसमें गरीब देश महाशक्तियों के आर्थिक शिंकजे की दासता में उलझ जाते हैं। इसका प्रभाव उनकी राजनीतिक संप्रभुता पर भी पड़ता है। विकास के नाम पर चीनी कर्ज के कारण श्रीलंका की संप्रभुता पर संकट गहरा गया है।

विकासशील देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली की यह लोकप्रिय मान्यता रही है कि जनता करिश्माई नेतृत्व को संपूर्ण सत्ता सौंप कर खुशियां ढूंढ़ती है। आर्थिक-सामाजिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक टकराव, राजनीतिक अस्थायित्व और जातीय विविधता तीसरी दुनिया के देशों की बड़ी समस्या रही है। यहां अतिलोकप्रिय नेतृत्व उभरने से अधिनायकवाद के पनपने का खतरा बढ़ जाता है। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका अतिराष्ट्रवादी राजपक्षे परिवार के सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखने और विपक्ष को दरकिनार करने की सत्तारूढ़ पार्टी की चेष्टा से गहरे संकट में फंस गया है। महंगाई दर में अभूतपूर्व वृद्धि और रोजमर्रा की चीजों के भाव आसमान छूने से लोगों में गुस्सा और हताशा बढ़ गई है। इसकी परिणति आज देश में हिंसा और आगजनी के रूप में सामने आई है। आपातकाल और कर्फ्यू से बेपरवाह लोग हिंसक प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। इस प्रकार एक बार फिर श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ने की आशंका गहरा गई है।

दरअसल, तमिलों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को दबा कर और सिंहली राष्ट्रवाद को उभार कर सत्ता में जमा बैठा राजपक्षे परिवार काफी समय से लोकतंत्र की मूल मान्यताओं को नजरअंदाज करता रहा है। लोकतंत्र सलाह, समन्वय और सहयोग से मजबूत होता है, जबकि करिश्माई नेतृत्व में आधिपत्यवादी प्रवृति को बढ़ावा मिलने की संभावना बनी रहती है।

राजपक्षे परिवार ने अतिराष्ट्रवाद को राजनीतिक हथियार की तरह प्रयुक्त कर लोगों का भरोसा जीता और बाद में राष्ट्रहित की विपक्षी दलों की सलाह को दरकिनार कर चीन से एकतरफा समझौते कर लिए। इन्हीं समझौतों के कारण देश आर्थिक बदहाली के दुष्चक्र में उलझ गया। श्रीलंका में 2009 में एलटीटीई की समाप्ति से राजपक्षे परिवार की लोकप्रियता में अभूतपूर्व इजाफा हुआ था।

महिंदा राजपक्षे ने सिंहली राष्ट्रवाद को श्रीलंका की अस्मिता से जोड़ कर सत्ता पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। सिंहली बहुल इस देश में तमिल और भारत विरोध राजपक्षे की प्रमुख नीतियां रहीं और इसका फायदा चीन ने उठाया। राजपक्षे सरकार के चीनी कर्ज और गलत आर्थिक प्रबंधन ने संकट और बढ़ा दिया। इससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। इस समय श्रीलंका चीन के भारी कर्ज तले दबा है। ऐसे में यह अंदेशा है कि कर्ज न चुका पाने की स्थिति में चीन श्रीलंका के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर सकता है।

राजपक्षे सरकार देश के आर्थिक माडल को बदल देने की योजनाओं को आगे बढ़ा रही थी। इसी में वह छोटे किसानों के हितों की अनदेखी करके जैविक खेती के चीन के व्यापारिक माडल में उलझ गई। सरकार ने रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे कृषि क्षेत्र पर बुरा असर पड़ा और कृषि अर्थव्यवस्था चौपट होती चली गई।

चीन ने अपनी वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत भी श्रीलंका को अरबों डालर का कर्ज दे रखा है। राजपक्षे परिवार के प्रभाव में संसद ने पोर्ट सिटी इकोनामिक कमीशन बिल भी पारित किया था। यह बिल चीन की वित्तीय मदद से बनने वाले इलाकों को विशेष छूट देता है। विशेष आर्थिक जोन विकसित करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के नाम पर बनाए गए इन कानूनों को लेकर न तो विपक्षी दलों से बात की गई और न ही देश में आम राय कायम करने की कोशिश की गई। इससे नाराज विपक्षी दलों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ किसानों और जनता को लामबंद करना शुरू कर दिया।

राजपक्षे की श्रीलंका फ्रीडम पार्टी को देश में व्यापक जन समर्थन हासिल था। इसका प्रमुख कारण महिंदा राजपक्षे और उनके छोटे भाई गोटभाया की तमिलों के प्रति कड़ी और नफरतभरी नीतियां थीं। बाद में राजपक्षे ने श्रीलंका में सिंहली राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और इसी के सहारे उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। विपक्षी यूनाइटेड नेशनल पार्टी की घटती लोकप्रियता से श्रीलंका में राजपक्षे परिवार मजबूत हो गया और यहीं से पनपा सत्ता का अधिनायकवाद मुल्क की आर्थिक बर्बादी का कारण बन गया।

लोग जब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे तो सरकार दमन पर उतर आई और इस दमनकारी नीति का असर लोगों के गुस्से के रूप में दिखने लगा। राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की तो इससे पुलिस को बिना वारंट लोगों को हिरासत में लेने और सोशल मीडिया को बंद करने का अधिकार मिल गया। श्रीलंका की बिगड़ती स्थिति का प्रमुख कारण चीन की ऊंची ब्याज दर है। कर्ज लौटाना तो दूर की बात है, ब्याज के भुगतान के लिए भी श्रीलंका को और कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसे में लोक कल्याणकारी योजनाएं बंद हो गई हैं।

यह देखा गया है कि चीन अपनी अंतरराष्ट्रीय विकास परियोजनाओं के लिए जरूरी वित्त ीय प्रतिबद्धताओं के लिए अमेरिका और दुनिया के दूसरे कई प्रमुख देशों की तुलना में लगभग दोगुनी धनराशि खर्च करता है। इनमें से ज्यादातर धनराशि राष्ट्रीय बैंकों से उच्च ब्याज दर के जोखिम पर कर्ज के रूप में ली जाती है। विकास के नाम पर दी जाने वाली इस राशि को लेकर शुरुआत में यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि कर्ज से उनकी प्रगति किस हद तक प्रभावित होगी।

भारत की तमाम कोशिशों के बाद भी श्रीलंका इस तथ्य को दरकिनार करता रहा है कि भारत से सांस्कृतिक और भौगोलिक निकटता सामरिक दृष्टि से भी उसके लिए ज्यादा असरदार साबित होती है। चीन के गहरे व्यापारिक हित श्रीलंका में है। चीन और श्रीलंका के बीच दक्षिण समुद्री बंदरगाह हंबनटोटा को लेकर अरबों डालर का समझौता भारत की अनदेखी करने की श्रीलंका की नीति के कारण ही हुआ था। श्रीलंका में चीन की अनेक परियोजनाएं चल रही है और उसने श्रीलंका को तकरीबन डेढ़ सौ करोड़ डालर का कर्ज भी दे रखा है। मध्यपूर्व से होने वाले तेल आयात के रूट में श्रीलंका एक अहम पड़ाव है, इसीलिए चीन की यहां निवेश करने में रुचि है।

भारत के लिए श्रीलंका से मजबूत संबंध सामरिक और सांस्कृतिक तौर पर भी बेहद जरूरी हैं। श्रीलंका की अस्थिरता भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी संकट बढ़ा सकती है। वहां रहने वाले तमिलों के भारत से गहरे रिश्ते हैं। वे कई दशकों से श्रीलंका में उत्पीड़न झेलने को मजबूर हैं। श्रीलंका में सिंहल बहुसंख्यकों द्वारा उत्पीड़ित श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी भारत में पनाह के लिए आते हैं और इसका प्रभाव भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु पर पड़ना स्वाभाविक है जो ऐतिहासिक रूप से तमिलों की मातृभूमि समझी जाती है।

श्रीलंका द्वीप का उत्तरी भाग भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट से मात्र कुछ किलोमीटर दूर है और तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले से जाफना प्रायद्वीप तक का समुदी सफर छोटी-छोटी नौकाओं में आसानी से प्रतिदिन लोग करते हैं। श्रीलंका की आबादी का लगभग बीस फीसद तमिल हैं और वे भारतीय मूल के हैं। भारत के दक्षिणी तमिलनाडु राज्य से इन तमिलों के रोटी और बेटी के संबंध हैं। भारत श्रीलंका को लेकर मित्रवत व्यवहार करता रहा है और आज भी कर रहा है।

श्रीलंका का संकट नव उपनिवेशवाद की चुनौतियों को सामने लाने वाला है, जिसमें गरीब देश महाशक्तियों के आर्थिक शिंकजे की दासता में उलझ जाते हैं। इसका प्रभाव उनकी राजनीतिक संप्रभुता पर भी पड़ता है। विकास के नाम पर चीनी कर्ज के कारण श्रीलंका की संप्रभुता पर संकट गहरा गया है। फिलहाल इस देश में शांति बहाल करने के लिए वहां सर्वदलीय सरकार के साथ देश के लोकप्रिय क्रिकेटरों, कलाकारों और भारत के सहयोग की दरकार है।

जीरो वेस्ट की दिशा में कैसे बढ़ेगा हिंदुस्तान

(अनु जैन रोहतगी)

दिल्ली की भलस्वा लैंडफिल में सुलगती आग बुझाए नहीं बुझ रही है। लैंडफिल या जगह-जगह इकट्ठे कूड़े में आग की समस्या से सिर्फ दिल्ली नहीं जूझती, देश के ज्यादातर इलाकों में ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। इस सुलगती समस्या के पीछे छुपे मूल कारण को समझने और सुलझाने की सख्त जरूरत है।

यह एक कड़वा सच है कि जिस तेजी से देश में कूड़े का ढ़ेर बढ़ रहा है, कूड़ा प्रबंधन उतना ही सुस्त है। विश्व बैंक की वाट ए वाट्स 2.0' रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि देश में हर साल 27.71 करोड़ टन कूड़ा निकलता है। यह साउथ एशिया देशों का 80 फीसदी कूड़ा है। दुनिया भर का 13 फीसदी कूड़ा सिर्फ भारत में ही पैदा होता है। कूड़ा प्रबंधन नीति, साधन और जागरूकता का अभाव ही है कि कुल कूड़े का लगभग 77 फीसदी हिस्सा खुले में फेंका जाता है। सिर्फ 5 फीसदी कूड़ा रीसाइक्लिंग के लिए पहुंचता है और 18 फीसदी कूड़े को कंपोज किया जाता है।

आने वाले समय में स्थिति और खराब होने वाली है। विश्व बैंक की रिपोर्ट यह भी बताती है कि वर्ष 2030 तक 38.78 करोड़ टन और 2050 तक 54.33 करोड़ टन कूड़ा भारत में पैदा होगा। विश्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि इस समय दुनिया भर से लगभग 2 अरब टन कूड़ा निकलता है। 2050 तक यह 3.4 अरब टन हो जाएगा। चिंताजनक बात यह है कि अविकसित देशों में 90 फीसदी कूड़ा प्रबंधन नहीं हो पाता है। कूड़ा प्रबंधन में होने वाली खामियों का सीधा असर पर्यावरण पर पड़ता है।

भारत में कूड़ा प्रबंधन के नाम पर अभी तक ज्यादातर कूड़े को खुले में डालने और जलाने का तरीका ही अपनाया जाता है। इससे देश में प्रदूषण स्तर के साथ-साथ ढेरों समस्याएं भी बढ़ रही हैं। स्विस ऑर्गनाइजेशन की 'वर्ल्ड एयर क्वॉलिटी रिपोर्ट 2020? के मुताबिक दुनिया के 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 22 भारत में ही हैं। अस्थमा, कैंसर, अविकसित बच्चों की पैदाइश, इंफर्टिलिटी आदि के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई अध्ययन इसका सीधा संबंध वायु प्रदूषण से जोड़ रहे हैं। जेएनयू की एक रिपोर्ट बताती है कि लैंडफिल में जमा कूड़े में जिंक, लेड, निकल, क्रोमियम जैसे जहरीले पदार्थ होते हैं। रिस कर ये हमारे ग्राउंडवाटर तक पहुंच जाते हैं। पानी के साथ ही ये मिट्टी को भी जहरीला बना रहे हैं।

भारत भर में मौजूद लगभग 1700 लैंडफिल में से ज्यादातर कूड़े से भर चुके हैं। सही प्रबंधन के अभाव में यहां ढेरों समस्याएं पैदा हो रही हैं। आग लगना ऐसी ही एक समस्या है। समय की मांग है कि कूड़ा प्रबंधन के काम में कोताही ना बरती जाए। शुरुआत हम घर से कर सकते हैं। घरों में गीले-सूखे और खतरनाक कूड़े को अलग-अलग करके कूड़ा प्रबंधन में एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। चीजों को फेंकने की बजाय उसे ठीक कराना, कूड़े को दोबारा इस्तेमाल करने योग्य बनाना, पेपरवर्क की जगह तकनीक के इस्तेमाल जैसे कुछ तरीके हैं जिनसे कूड़ा कम किया जा सकता है। कई विकसित देशों ने इन्हीं तरीकों से अपने कूड़ा प्रबंधन को गति दी है। इस मामले में जर्मनी ने लीड ली हुई है। वहां हर साल 10 लाख टन कूड़ा कम हो रहा है। स्वीडन भी जीरो वेस्ट की दिशा में बड़ा काम कर रहा है।

हालांकि भारत सरकार ने दो अक्टूबर 2014 को देश में स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था। कूड़े से निपटने के लिए इसके तहत अभी तक कई कारगर कदम उठाए गए हैं। 20 शहरों को वेस्ट फ्री करने की शुरुआत की गई है। कई शहरों जैसे सूरत, पूना, एलीपी-केरल, बोबीली-आंध्र प्रदेश में कूड़ा निपटारे को लेकर काफी अच्छे काम चल रहे हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में जहां 18 फीसदी वेस्ट प्रोसेस किया जाता था, वर्ष 2021 में यह 70 फीसदी तक पहुंच गया है। इसे 100 फीसदी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन मंजिल बहुत दूर है, और इसे पाने के लिए सरकार के साथ-साथ हमें भी कूड़े की छंटनी से लेकर इसे कम से कम करने के तरीकों पर ध्यान देना होगा। ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं।

हमें ही नहीं, संतूर को भी उदास कर गए शिव कुमार शर्मा

दुनिया के सबसे प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जब भी इलाहाबाद आते थे, मेरे पिता पंडित भोलानाथ प्रसन्ना से जरूर मिलते थे। मेरे पिता प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु थे...

हमें ही नहीं, संतूर को भी उदास कर गए शिव कुमार शर्मा

(अजय प्रसन्ना, बांसुरी वादक)

अपने बचपन से मैं उन्हें देखता आ रहा था। अब सोच भी नहीं पा रहा हूं कि वह इस दुनिया में नहीं हैं और मैं उन्हें अब नहीं देख सकूंगा। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जब भी इलाहाबाद आते थे, मेरे पिता पंडित भोलानाथ प्रसन्ना से जरूर मिलते थे। मेरे पिता प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु थे। इस नाते भी शिव कुमार शर्मा पिता का बहुत आदर करते थे। आज मुझे कई पुरानी बातें, मुलाकातें सिलसिलेवार याद आ रही हैं। मेरे बचपन का दौर था, करीब छह-सात साल मेरी उम्र रही होगी। कुछ-कुछ होश संभालने लगा था। तब मेरा सौभाग्य रहा कि एक दिन पंडित जी मेरे पिता से मिलने आए। पिता के सामने ही मेरा बांसुरी वादन उन्होंने सुना और बोल पड़े, 'यह तो छोटा हरि है'। उनकी प्रशंसा का असर आज भी है। उनका मन निश्छल था, वह हमेशा अपने मन की बात कहते थे।

अब जब उनके न रहने की खबर आई है, तो सदमा सा लगा है। पद्म विभूषण व संगीत के तमाम पुरस्कारों से सम्मानित शिव कुमार शर्मा का न होना इस देश के लिए एक बड़ी क्षति है। भारतीय शास्त्रीय संगीत संसार ने अपने सबसे चमकदार सितारों में से एक को खो दिया है। उनके न होने से असंख्य संगीत प्रेमियों को जो क्षति पहुंची है, उसकी भरपाई अब शायद नहीं हो सकेगी। उनके साथ कई बार विश्व भर में मंच साझा करने का मुझे मौका मिला। लंदन में मेरे संगीत अलबम की रिलीज में हम कई दिनों तक साथ रहे थे। उन्होंने ही बहुत चाव-लगाव से मेरे अलबम का विमोचन किया था। वह बहुत प्रसिद्ध हस्ती होने के बावजूद अत्यंत सरल स्वभाव के थे। जमीन से जुड़े थे, लोगों से आसानी से मिलते थे और खुश रहते थे। वह खुशी उनके संगीत में भी झलकती है। उनका सच्चा संगीतमय व्यक्तित्व बहुतों के मन में हमेशा छाया रहेगा। वह सच्चे शास्त्रीय संगीत साधक थे और कभी भी गुणवत्ता या संगीत के स्तर से उन्होंने समझौता नहीं किया। आप याद कीजिए, मैं तो अभी भावविभोर हूं कि उनके तपस्वी से मुख पर कैसा तेज रहता था, जो हर देखने वाले को भी जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता था। हर बार मिलकर उनसे कुछ सीखना और समझना, लेकिन अब सब याद भर रह गया है। जब कोई संगीत के बारे में सीखना या जानना चाहता, तो वह उदार मन से सिखाते थे। मुझे याद है, लंदन में ही होटल में एक साथ बैठकर उन्होंने संगीत के अद्भुत गुर सिखाए थे। उन्होंने बहुत प्यार से बताया था कि किस प्रकार शास्त्रीय संगीत को सुगम बनाया जाता है और किस प्रकार फिल्म संगीत में भी शास्त्रीय मधुरता ला सकते हैं। उन्होंने हरिप्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर फिल्म संगीत में जो मधुर प्रयोग किए थे, वह अद्भुत काम हमेशा दुनिया के सामने एक मानक रहेगा। आज भी लोग सिलसिला, फासले, चांदनी, लम्हे, डर जैसी फिल्मों के संगीत का आनंद लेते हैं। न अब वैसा मौलिक संगीत कोई देता है और न यश चोपड़ा जैसे संगीत प्रेमी फिल्मकार हैं, जो शास्त्रीय संगीत और संगीतकारों को अच्छे से समझते थे। शिव-हरि का संगीत यश चोपड़ा की फिल्मों में जरूर गया, लेकिन संगीत की मूल गरिमा कदापि कम नहीं हुई। न हरिप्रसाद चौरसिया झुकने वाले संगीतकार थे और न पंडित शिव कुमार शर्मा ने कभी संगीत से समझौता किया। उनका एक और विशेष गुण मैं बताऊं? उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। छोटी से छोटी चीजें-बातें भी उन्हें याद रहती थीं। कई बार तो बहुत पुरानी बातें भी वे याद दिला जाते। सच यही है कि पंडित शिव कुमार शर्मा ने एक लोक वाद्य को खूबसूरती से विकसित किया और दुनिया में संतूर की पहचान बन गए। आज पूरी दुनिया संतूर को जानती है और सुनती है, इसका श्रेय उन्हें सदैव दिया जाएगा। दुनिया भर से उनके लिए बुलावा आता था और वह देश में तो बहुत दुलारे थे ही। उनका संगीत विभिन्न माध्यमों से आम लोगों तक पहुंचा और संतूर का समाज भी बड़ा हुआ। उनकी रगों में संगीत था। अपने पिता की छत्रछाया में उन्होंने तबला और गायन से शुरुआत की थी और किशोरवय में संतूर तक पहुंचे थे। उनके पुत्र राहुल शर्मा भी बहुत अच्छे संतूर वादक हैं।

जयपुर में होने वाले एमटीवी के म्यूजिक समिट में उनसे मेरा अंतिम बार मिलना हुआ था और हमने बहुत ही अच्छे पल साथ-साथ बिताए थे। अभी कुछ ही दिन पूर्व पंडित जी से मुंबई आकर मिलने और उनका आशीर्वाद लेने की बात हुई थी। आज वह नहीं हैं, लेकिन हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे। एक असाधारण व्यक्तित्व और कलाकार का चले जाना हमारे लिए अपूरणीय क्षति है। उनको स्मरण कर उनके चरणों में कोटि-कोटि नमन! (ये लेखक के अपने विचार हैं)

देशद्रोह को फिर समझने की कवायद

यह औपनिवेशिक काल का कानून है, जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश साम्राज्य में होता था। स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज इससे कुचली जाती थी और उनके आंदोलन को विफल करने के प्रयास होते थे। मगर आज हमारा राजनीतिक और सामाजिक परिवेश पूरी तरह से बदल चुका है। देश अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। ऐसे में, इस कानून का भला क्या औचित्य है? यह सवाल विभिन्न प्रकार की जनहित याचिकाओं में सर्वोच्च अदालत के सामने उठाए गए हैं। इसकी वजह थी पिछले कई वर्षों से इस कानून का हो रहा दुरुपयोग। न सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने और उनको परेशान करने के लिए, बल्कि आलोचना के स्वर को शांत करने के लिए भी इसका जमकर इस्तेमाल हो रहा है।

(पवन दुग्गल, साइबर कानून विशेषज्ञ)

भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (ए) में उन प्रावधानों का जिक्र है, जिनसे किसी शख्स को देशद्रोही साबित किया जाता है। यदि आप ऐसा कोई काम करते हैं, जो अपने शब्दों (चाहे वे लिखित हों या मौखिक) से या परिणामों से भारत सरकार के प्रति विरोध जताता है या लोगों को भारत सरकार के खिलाफ करने की कोशिश करता है, तो वह देशद्रोह कानून के दायरे में आता है। इसमें कैद (जो आजीवन भी हो सकती है), जुर्माना या दोनों तरह की सजा के प्रावधान हैं। अगर इस कानून के तहत कोई दोषी साबित हो गया, तो उसे कम से कम तीन साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों तरह की सजा मिलेगी ही।

यह औपनिवेशिक काल का कानून है, जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश साम्राज्य में होता था। स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज इससे कुचली जाती थी और उनके आंदोलन को विफल करने के प्रयास होते थे। मगर आज हमारा राजनीतिक और सामाजिक परिवेश पूरी तरह से बदल चुका है। देश अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। ऐसे में, इस कानून का भला क्या औचित्य है? यह सवाल विभिन्न प्रकार की जनहित याचिकाओं में सर्वोच्च अदालत के सामने उठाए गए हैं। इसकी वजह थी पिछले कई वर्षों से इस कानून का हो रहा दुरुपयोग। न सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने और उनको परेशान करने के लिए, बल्कि आलोचना के स्वर को शांत करने के लिए भी इसका जमकर इस्तेमाल हो रहा है। आलम यह है कि अगर कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहा हो, तो उसके ऊपर भी देशद्रोह कानून लगा दिया जाता है, जिसका न कोई औचित्य है और न धारा 124 (ए) का कोई प्रावधान उस पर लागू होता है।

सुप्रीम कोर्ट इस कानून के दुरुपयोग को लेकर ही चिंतित था। 2021 में भी उसने एक सुनवाई के दौरान सरकार से इसको निरस्त करने को कहा था। उसके तर्क थे कि इनमें जिन प्रावधानों का जिक्र है, वे औपनिवेशिक युग के हैं, जो स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इस्तेमाल होते थे। आज माहौल बदल चुका है और कोविड-19 के बाद ज्यादातर भारतीय इंटरनेट पर हैं। चूंकि भारत इंटरनेट की दुनिया में सबसे बड़े बाजार के रूप में उभर रहा है, इसलिए इस कानून के दायरे को या तो छोटा करना चाहिए या फिर इनमें संशोधन होना चाहिए। शायद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मूड को अब जाकर पढ़ा है, क्योंकि हाल-फिलहाल तक वह इस कानून का समर्थन कर रही थी। माना जा रहा है कि सरकार के अचानक यू-टर्न की वजह तीन जजों की खंडपीठ का वह कथन है, जिसमें उसने 10 मई, 2022 को इस पर बहस सुनने की बात कही थी कि यह मामला पांच जजों की पीठ के पास जाना चाहिए अथवा नहीं? सरकार को जब लगा कि यह मामला सांविधानिक पीठ के हवाले किया जा सकता है,

जिससे उसके सामने असहज परिस्थिति पैदा हो सकती है, तो उसने इस कानून की तत्काल समीक्षा करने की बात कही। शीर्ष अदालत ने भी सरकार की दलील को मान लिया है।

जब इस कानून की समीक्षा की बात होती है, तो तीन तरह की सोच सामने दिखती है। पहली, इस तरह के कानूनी प्रावधान खत्म कर देने चाहिए, क्योंकि इनकी अब कोई प्रासंगिकता नहीं बची। दूसरी, इस कानून को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि देश को इसकी सख्त जरूरत है, खासकर राष्ट्रविरोधी ताकतों को देखते हुए। और तीसरी सोच उन लोगों की है, जो मानते हैं कि यह कानून तो कायम रहना चाहिए, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसके इस्तेमाल पर कुछ वाजिब अंकुश लगाया जाना चाहिए। इस सोच के समर्थक मानते हैं कि अगर कानूनी किताब से इसे पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, तो देश की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को नुकसान पहुंच सकता है।

जाहिर है, सरकार इनमें से तीसरे विकल्प को चुन सकती है, क्योंकि हर हुकूमत इस तरह के कानून की हिमायती दिखती है। उसका मानना है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के हितों के खिलाफ काम करता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। मगर हां, इस कानून के पंख जरूर काटे जा सकते हैं। संभव है कि इसमें 'चेक ऐंड बैलेंस' का भी प्रावधान बने। सरकारों को यह समझना होगा कि उनकी आलोचना देशद्रोह के दायरे में नहीं आती। इसके अलावा, उन सीमित परिस्थितियों को भी परिभाषित किया जाना चाहिए, जिनमें इस कानून के इस्तेमाल की अनुमति हो सकती है। फिर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सरकार अपनी मनमानी करे। अगर सरकारों को देशद्रोह निर्धारित करने का पूरा अधिकार दे दिया जाएगा, तो उनके तमाम आलोचक देशद्रोही ठहरा दिए जा सकते हैं। इसलिए, जिस तरह से संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिले स्वतंत्र अभिव्यक्ति संबंधी मौलिक अधिकार पर कुछ बंदिशें हैं, उसी तरह से देशद्रोह कानून को आयद किए जाने संबंधी परिस्थितियों पर भी कुछ अंकुश जरूर लगने चाहिए। साफ है, इस कानून के औचित्य पर किंतु-परंतु का कोई सवाल नहीं है। वैसे भी, देश के अंदर और बाहर इतने 'नॉन-स्टेट एक्टर्स' काम कर रहे हैं कि भारत की स्थिरता को हमेशा खतरा बना रहता है। ऐसे में, इस कानून की जरूरत हमें हर वक्त पड़ेगी। मगर हां, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निर्दोष नागरिकों के खिलाफ इसका बेजा इस्तेमाल नहीं हो। इसकी हरसंभव कोशिश होनी चाहिए कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो, और इसकी जिम्मेदारी स्वाभाविक तौर पर सरकार की होनी चाहिए। उसे इस तरह से सामंजस्य बनाना होगा कि एक तरफ उसके हितों की रक्षा हो सके, तो दूसरी ओर लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। सरकार यह 'गोल्डन बैलेंस' किस तरह बनाती है, इस पर नजर बनी रहेगी। हालांकि, हर राष्ट्र यही चाहता है कि वह ऐसे प्रावधान बनाए रखे, जो उसके हितों को चोट पहुंचाने वाली ताकतों के खिलाफ कारगर हो। अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर जैसे उन्नत देशों में भी देशद्रोह कानून जैसे प्रावधान हैं। जाहिर है, अपने देश में इस कानून की समीक्षा एक सराहनीय कदम है, और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का परिचायक भी है, जो औपनिवेशिक काल के कानूनों के खिलाफ हमेशा मुखर रहे हैं।(ये लेखक के अपने विचार हैं)

प्रतिदिन मेडिटेशन करना क्यों है जरुरी ?

आम धारणा के विपरीत, मेडिटेशन अपने विचारों या दिमाग को अलग-थलग करने और खाली करने के बारे में नहीं है। यह खुद के अंदर की ओर जाने, अपने विचारों को स्वीकार करने और फिर बिना किसी निर्णय के उनसे अलग होने के बारे में है।

मूल बातें से शुरू करें। अपने शरीर को बुनियादी सरल आसन (योग स्ट्रेच) के माध्यम से तैयार करके शुरू करें और प्राणायाम (श्वास तकनीक) के माध्यम से सांस लें। ऐसी जगह खोजें जो आपके लिए ध्यान करने के लिए आरामदायक हो। कुछ लोग घर या ऑफिस में शांत जगह का इस्तेमाल करते हैं। आप प्रकृति में बाहर भी ध्यान कर सकते हैं।

ध्यान तनाव, चिंता और नकारात्मक भावनाओं को कम करता है ध्यान एक उपहार है जिसे आपको हर दिन खुद को समर्पित करना चाहिए। तनाव को कम करने में मदद करने के लिए अपनी सांस का प्रयोग करें और इस समय अधिक जागरूक और उपस्थित बनें। तनाव, चिंता और नकारात्मक भावनाएं अप्रत्याशित होती हैं, वे अपनी मर्जी से आती हैं और चली जाती हैं लेकिन ध्यान के माध्यम से, आप अपने और अपने दिमाग पर उनकी शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। समय के साथ आप अपने भीतर जमा होने वाले तनाव/चिंता की मात्रा में परिवर्तन देखेंगे। बस अपनी आंखें बंद करने और लगातार सांस लेने से जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, खासकर जब आप तनावपूर्ण स्थितियों को उत्पन्न होने की पहचान करते हैं। चिंता को कम करने के लिए ध्यान इतना शक्तिशाली है। लोगों के ध्यान करने के मुख्य कारणों में से एक है एक जोरदार, अति सक्रिय दिमाग को शांत करने में मदद करना। दैनिक ध्यान उपचार का समर्थन करने और चिंता और अवसाद के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ध्यान तनाव और चिंता से लड़ने में मदद करता है, जो दोनों ही अवसाद के प्रमुख ट्रिगर प्वाइंट हैं।

यह फोकस, रचनात्मकता और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है, काम पर अधिक रचनात्मक और उत्पादक महसूस करना चाहते हैं? अब ध्यान करना शुरू करें! ध्यान रचनात्मक सोच और समस्या-समाधान को प्रोत्साहित कर सकता है। ध्यान हमें अपनी भावनाओं को अपने काम से अलग करने में भी मदद करता है, जो हमें अधिक स्पष्ट रूप से सोचने और नए विचारों को विकसित करने में मदद करता है। दैनिक ध्यान आपको काम में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकता है! यह आपका ध्यान बढ़ाने में मदद करता है और मल्टीटास्क करने की आपकी क्षमता में सुधार करता है। ध्यान हमारे दिमाग को साफ करने में मदद करता है और हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है - जो आपको एक बड़ी उत्पादकता को बढ़ावा देता है।

यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है

जब तक आप अपने विचारों का निरीक्षण करने का प्रयास नहीं करते हैं और यह समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि मन क्या कर रहा है, आप कभी भी अपने आंतरिक मन के बारे में नहीं जान सकते। हममें से कई लोगों को अपनी भावनाओं को समझने में परेशानी होती है। ध्यान हमें अपनी भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक होना सिखाता है और हमें उन्हें बेहतर तरीके से संसाधित करने में मदद करता है।

नींद में सुधार

विभिन्न प्रकार की ध्यान तकनीकें आपके नींद चक्र में बाधा डालने वाले भगोड़े विचारों को आराम और नियंत्रित करने में आपकी मदद कर सकती हैं। यह सोने में लगने वाले समय को कम कर सकता है और आपकी नींद की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है।

व्यसनों से लड़ने में मदद करता है

ध्यान मानसिक जागरूकता विकसित करता है और अवांछित आवेगों को प्रबंधित करने में आपकी सहायता कर सकता है। यह आपको व्यसन से उबरने, अस्वास्थ्यकर खाने की आदतों को प्रबंधित करने और अन्य अवांछित आदतों को पुनर्निर्देशित करने में मदद कर सकता है।

प्रतिरक्षा को बढ़ाता है

नियमित ध्यान आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह मस्तिष्क के बाईं ओर इलेक्ट्रिकल गतिविधि को बढ़ाता है - जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेदार है। यह भी पाया गया कि जो लोग ध्यान करते हैं उनके रक्त में एंटीबॉडी की मात्रा अधिक होती है, जो बीमारी से लड़ने में मदद करती है।

हंसी आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद करती है

पिछली बार कब आप जोर से हंसे थे? हंसी न केवल आपको अच्छा महसूस कराती है, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाती है। हंसी तनाव के कई नकारात्मक लक्षणों को कम करती है। जब आप हंसते हैं, तो आपका शरीर एंडोर्फिन पैदा करता है, जो फील-गुड हार्मोन हैं। ये हार्मोन आपको अच्छा महसूस कराते हैं और नकारात्मक भावनाओं को दूर रखते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप हंसने के बाद बेहतर महसूस करते हैं। हंसी आपके दिल की देखभाल करने का एक आसान तरीका है। इसके लिए जीवनशैली में भारी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह आपको अपने जीवन में खुशियों की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

हंसी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की ताकत को बढ़ाती है। हंसने से आपके शरीर में रोग से लड़ने वाली कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे आपके बीमार या संक्रमित होने की संभावना कम हो जाती है। यदि आप अस्वस्थ हो जाते हैं, तो आपका शरीर इससे निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होगा।

हंसना दिल का दौरा पड़ने की संभावना को कम करता है। जब आप हंसते हैं तो आपकी हृदय गति बढ़ जाती है और आप कई गहरी सांसें लेते हैं। यह आपके शरीर के माध्यम से अधिक ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रसारित करने की अनुमति देकर संवहनी कार्य में सुधार करता है।

हृदय रोग की शुरूआत को रोकता है। बेहतर संवहनी कार्य और परिसंचरण भी हृदय रोग से निदान होने की संभावना को कम कर सकते हैं। यदि रक्त प्रवाह पर्याप्त है तो आपका हृदय नियमित लय में धड़कता रहेगा।

यह वजन घटाने में मदद करता है। कोर्टिसोल, एक तनाव हार्मोन, वजन बढ़ा सकता है और यदि आप बहुत अधिक तनाव करते हैं तो आपके स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। शरीर में कोर्टिसोल का उच्च स्तर तेजी से वजन बढ़ने का कारण बन सकता है। हंसने से न सिर्फ तनाव कम होता है, बल्कि कैलोरी भी बर्न होती है। जब एक हृदय-स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम के साथ जोड़ा जाता है, तो आपके पास भविष्य में हृदय की समस्याओं से बचने का एक बेहतर मौका होगा!

रक्तचाप कम हो जाता है। आपका शरीर आराम करता है, आपके रक्तचाप को कम करता है, जबकि एंडोर्फिन तनाव रसायनों के हानिकारक प्रभावों का मुकाबला करने के लिए जारी किया जाता है। इन फील गुड रसायनों और निम्न रक्तचाप का संयोजन आपके मूड को बढ़ाता है, चिंता को कम करता है, और हृदय तनाव से राहत देता है। अपने जीवन में और अधिक हंसी जोड़कर अपनी खुशी बढ़ाएं और अपने हृदय स्वास्थ्य में सुधार करें। पता नहीं कहां से शुरू करें? एक अच्छा समय बिताने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए इन सुझावों को आजमाएं-

यदि आप नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे अपराध एपिसोड या नाटक देखते हैं, या यदि आप टीवी पर बहुत सारी खबरें या खेल देखते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप एक प्रफुल्लित करने वाली फिल्म या स्टैंड-अप कॉमेडी देखें।

कुछ स्थानीय इम्प्रोव या स्टैंड-अप कॉमेडी गिग्स ढूंढें और अनुभव का आनंद लें। अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताना मुस्कुराने का सबसे आसान तरीका है। एक मनोरंजक खेल रात का आयोजन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी के पास भाग लेने का मौका है, ऐसे गेम चुनें जो समूह जुड़ाव को प्रोत्साहित करते हैं।

चम्मच नहीं हाथ से खाना खाएं, रहेंगे स्वस्थ, ऐसे होगी मसल्स की एक्सरसाइज

कई भारतीय परंपराएं आज नहीं अपनाई जाती लेकिन इनके कई फायदे होते हैं। इन परंपराओं में से एक है हाथों से खाना खाना। इसे अब बदल दिया गया है और खाना खाने के लिए कटलरी का उपयोग किया जाता है। हालांकि लोगों ने भले ही खाना खाने के लिए चम्मच और कांटे उठा लिए हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग अपना खाना हाथों से खाना पसंद करते हैं। इसके पीछे के कारण केवल सदियों से चली आ रही परंपरा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य लाभ भी हैं। वहीं मॉर्डन जमाने में जहां लोगों को खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है ऐसे में अपनी परंपराओं को अपनाना सही फैसला साबित हो सकता है। हाथों से खाना खाने से ब्लड सरक्यूलेशन बढ़ता है। हाथों से खाना एक तरह की मसल्स की एक्सरसाइज है। हाथों को बार-बार हिलाने से ब्लड सरक्यूलेशन सही रहता है। हाथों से खाना खाने से पाचन ठीक रहता है। हमारे शरीर में बैक्टीरिया खाना पचाने में मदद करते हैं जो हाथ, मुंह, गले, आंत और आंत जैसी जगहों पर रहते हैं। जब हम हाथों से खाते हैं तो हम बाहर से आने वाले हानिकारक जीवाणुओं से बच जाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। हाथों से खाने से आप ये जान पाते हैं कि आप कितना खा रहे हैं। चम्मच से खाने पर इस बात का अंदाजा नहीं होता की कितना खा रहे हैं। ऐसे में हाथ से खाने पर खाने का स्वाद ज्यादा ले सकते हैं और अपने खाने को भी नियंत्रित कर सकते हैं।

जानिए भय के एक प्रकार फोनोफोबिया के बारे में

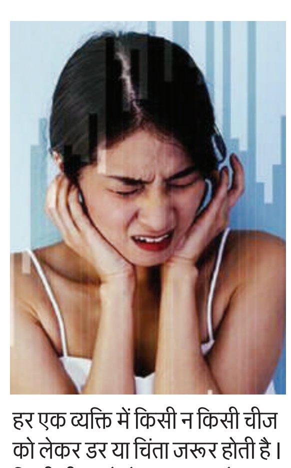

हर एक व्यक्ति में किसी न किसी चीज को लेकर डर या चिंता जरूर होती है। किसी चीज को लेकर डर हमारे जीवन की अन्य अहसासों की तरह ही है। भय किसी भी तरह के हो सकते हैं। आपने लोगों से जरूर सुना होगा कि उन्हें ऊंचाई से डर लगता है या किसी को गहरे पानी से डर लगता है। लेकिन जब यह डर सामान्य न रहे तो इसे फोबिया कहा जाता है। आज हम इस लेख में एक ऐसे ही फोबिया के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी फोनोफोबिया के बारे में सुना है?

फोनोफोबिया, जो अधिकतर छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। ऐसे लोग अचानक तेज आवाज से डर जाते हैं। लेकिन यदि बड़ों में यह समस्या हो तो ऐसे लोग किसी भी पार्टी, फंक्शन या घर से बाहर तक जाने में घबराते हैं। अगर फोन की रिंग बज जाए तो घबराहट व पसीना आना शुरू हो जाता है अर्थात किसी चीज की तेज आवाज जैसे फोन की रिंग बजना इसे उत्पन्न घबराहट को फोनोफोबिया कहा जाता है। फोनोफोबिया में व्यक्ति फोन पर बात करने से भी कतराता है। अगर फोन की आवाज सुनाई आए तो घबराहट और तेजी से सांस लेने लगता है। इस समस्या का उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है। फोनोफोबिया की वजह से घनघनाते रिंगटोन से और असमय के कॉल से एंग्जाइटी होती है। अमेरिका में 15 मिलियन लोगों में यह समस्या देखी गई है।

फोनोफोबिया के लक्षण

- तेज सिरदर्द
- तेजी से सांस लेना
- पसीना आना
- घबराहट होना
- हार्टबीट का बढ़ना

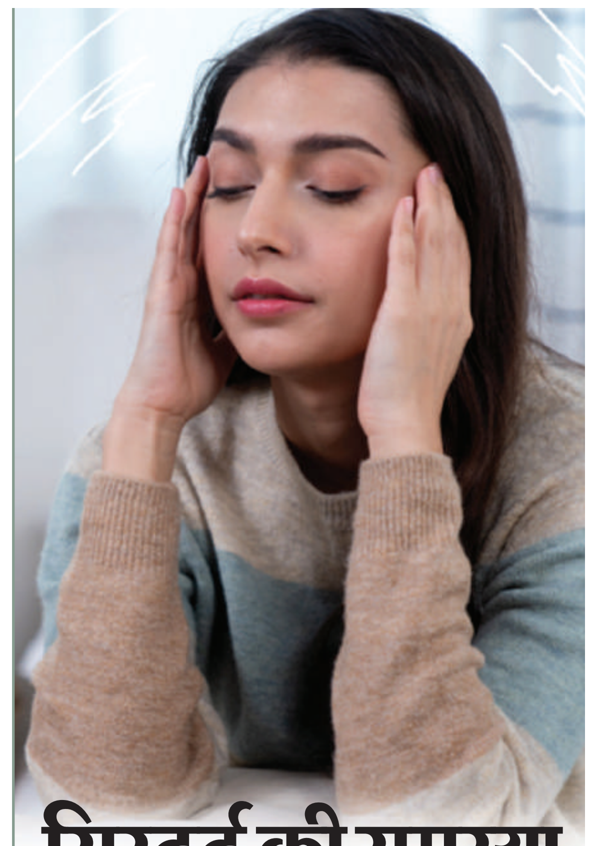

सिरदर्द की समस्या से महिलायें अधिक परेशान

दुनिया भर की 52 प्रतिशत से अधिक आबादी को हर साल सिरदर्द की समस्या से गुजरना पड़ता है, जिनमें से 14 प्रतिशत मामले माइग्रेन के होते हैं। ताजा शोध से यह भी खुलासा हुआ है कि पुरूषों की तुलना में महिलायें सिरदर्द से अधिक पीड़ित होती हैं। जर्नल ऑफ हेडेक एंड पेन में प्रकाशित नॉर्वे की साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की शोध रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में 20 से 65 साल के आयुवर्ग में सिरदर्द की समस्या अधिक पायी जाती है। शोधकर्ताओं ने 1961 से 2020 के बीच प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर सिरदर्द की समस्या का आकलन किया है। उनकी इस समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 26 प्रतिशत लोग तनाव संबंधी सिरदर्द से ग्रसित होते हैं और 4.6 प्रतिशत लोगों ने हर माह 15 या उससे अधिक दिन सिरदर्द होने की बात की। शोध से यह भी पता चला कि लगभग 15.8 प्रतिशत लोगों को कभी भी सिरदर्द होने लगता है और इनमें से करीब 50 फीसदी लोगों ने माइग्रेन की शिकायत की। शोध रिपोर्ट के मुख्य लेखक लार्स जैकब सोवनर ने कहा कि दुनिया भर में सिरदर्द की समस्या आम है और इसके अलग-अलग रूप से कई लोग प्रभावित हैं। सिरदर्द रोकने के और इसके उपचार के बेहतर उपाय ढूंढने की जरूरत है। शोध में कहा गया है कि महिलायें सिरदर्द से अधिक पीड़ित होती हैं। शोध में पाया गया कि 8.6 पुरूष माइग्रेन के शिकार होते हैं, वहीं 17 प्रतिशत महिलायें इससे पीड़ित होती हैं। इसी तरह छह प्रतिशत महिलाओं को 15 दिन या इससे अधिक दिन सिरदर्द की शिकायत होती है जबकि पुरूषों के मामले में इसका प्रतिशत 2.9 ही है।

ज्यादा टेंशन लेंगे तो मोटे हो जाएंगे

ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे यह कहावत हुई अब पुरानी, नई वाली है कि ज्यादा तनाव लोगे और तनाव में खाओगे तो मोटे हो जाओगे.... जरूरत से ज्यादा तनाव लेने से भी व्यक्ति मोटापे का शिकार बन सकता है। तनाव से झेलने पड़ सकते हैं ये साइड इफेक्ट्स।

- तनाव दूर करने के लिए व्यक्ति को योग, मेडिटेशन जैसी एंटी स्ट्रेस तकनीक के अलावा पाचन को दुरुस्त बनाए रखने वाले खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके लिए आप फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे ओट्स, जौ, जामुन और राई अपनी डाइट में शामिल करें। मेवे और बीज तनाव को कम करने वाले एक बेहतरीन स्नैक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोटीन और गुड फैट के भी अच्छे स्रोत हैं।
- तनाव की वजह से व्यक्ति की भूख अनियंत्रित हो जाती है। जिसकी वजह से व्यक्ति या तो बहुत ज्यादा या फिर कम खाने लगता है। ज्यादा खाने से कैलोरी की मात्रा अधिक हो जाती है जबकि भूख से कम खाने से भी व्यक्ति का मेटाबोलिज्म स्लो हो जाता है। जिसकी वजह से वह मोटापे का शिकार हो सकता है। भूख का अनियंत्रित होना आपके ब्लड प्रेशर, शुगर, हड्डियों और पेट के सेहत को भी प्रभावित कर सकता है।
- तनाव की वजह से व्यक्ति का कोर्टिसोल और इंसुलिन प्रभावित होता है जिससे शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा होती रहती है। कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है। जिसके प्रभावित होने पर व्यक्ति के शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा होने लगती है।
- तनाव की वजह से आपकी पाचन क्रिया प्रभावित होती है। ये आपके मेटाबोलिज्म को स्लो करके गैस और बदहजमी जैसी समस्या पैदा करता है।
- तनाव की वजह से कई बार व्यक्ति को नींद न आने की समस्या, एसिडिटी के साथ मोटापे की समस्या भी होती है, ये सभी समस्याएं खराब पाचन तंत्र से जुड़ी हुई हैं।
- तनाव आपकी आंतों में रहने वाले गुड बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाकर उनहें नष्ट करता रहता है। जिसकी वजह से व्यक्ति का मेटाबोलिज्म प्रभावित होता है। मेटाबोलिज्म ठीक रखने के लिए जरूरी है कि आप स्ट्रेस से दूर रहें और अपने गुड बैक्टीरिया को हेल्दी रखें।
- जब तनाव का स्तर बढ़ता है, तो इसका सबसे ज्यादा असर हमारी थायरॉयड ग्रंथि पर पड़ता है। यह ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को बढ़ा देता है। थायराइड पर तनाव का असर पड़ने से व्यक्ति के शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है।
- स्ट्रेस दूर करने के लिए आप अपने आहार में बादाम, अखरोट, मेवे के साथ अलसी के बीज, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज आदि जैसे बीज नियमित रूप से शामिल करें।

कांग्रेस चिंतन शिविर में सोनिया गांधी का भाषण : कहा-

पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है अब कर्ज उतारने का समय

नई दिल्ली

उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के तीन दिवसीय चिंतन शिविर की वेलकम स्पीच में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा- पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब कर्ज उतारने का समय है। सोनिया ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को त्याग करके पार्टी हित में काम करने की नसीहत दी है। कांग्रेस कार्यसमिति में कही गई बात को आज खुले में दोहराई है। कहा- ऐसा समय आया है कि हमें संगठन हितों के अधीन काम करना होगा। सबसे आग्रह है कि खुलकर अपने विचार रखें, मगर बाहर एक ही संदेश जाना चाहिए संगठन की मजूबती, मजबूत निश्चय और एकता का ।सोनिया ने कहा- हमें मिली विफलताओं से हम बेखबर नहीं हैं। न हम बेखबर हैं संघर्ष और कठिनाइयों से जो हमें आगे करना है। लोगों की उम्मीदों से हम अनजान नहीं है। हमें यह प्रण लेने इकट्ठा हुए हैं,

हम देश की राजनीति में अपनी पार्टी को उसी भूमिका में लाएंगे जो सदैव निभाई है, जिस भूमिका की उम्मीद इस बिगड़ते समय में देश की जनता करती है। हम आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं। यह तय करें कि यहां से निकलें तो एक नए आत्मविश्वास और कमिटमेंट से प्रेरित होकर निकलेंगे।

असाधारण हालात का मुकाबला असाधारण तरीके से ही करें

सोनिया ने कहा- आज पार्टी के सामने असाधारण परिस्थितियां हैं। असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है। हर संगठन को जीवित रहने बढ़ने के लिए भी अपने अंदर पैनापन लाना होता है। हमें सुधारों की सख्त जरूरत है। हमें रणनीतिक बदलाव, ढांचागत सुधार और रोजाना काम करने के तरीके में बदलाव सबसे बुनियादी जरूरी मुद्दा है। हमारा उत्थान सामूहिक प्रयासों से ही हो पाएगा। ये प्रयास आगे टाले नहीं जा सकते। न आगे जा सकते हैं, न टाले जा सकते हैं यह प्रभावशाली कदम होगा।

बीजेपी देश में डर-असुरक्षा का माहौल पैदा कर रही:- उन्होंने BJP और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कहा- बीजेपी-केंद्र सरकार देश में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रही है। अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। धर्म के नाम पर पॉलराइजेशन किया जा रहा है। अल्पसंख्यक हमारे देश में बराबर के नागरिक हैं। यह हमारी पुरानी बहुलवादी कल्चर का परिचायक है। विविधता में एकता में हमारी पहचान रही है। सोनिया ने कहा- आज राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पंडित नेहरू के योगदान और देश के लिए त्याग को योजनाबद्ध तरीके से कम करके दिखाने का प्रयास हो रहा है। ये लोग महात्मा गांधी के हत्यारे का महिमामंडन कर रहे हैं और गांधी के सिद्धांतों को मिटा रहे हैं। उन्होंने कहा- देश के पुराने मूल्यों को खत्म किया जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर में 24 घंटे में दो टारगेट किलिंग

अब एसपीओ को घर में घुसकर गोली मारी कश्मीरी पंडित बोले- सरकारी दावे फेल

श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर में 90 के दशक में हुईं टारगेट किलिंग का दौर फिर लौट आया है। आतंकवादी जवानों के साथ कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं। शुक्रवार सुबह पुलवामा में आतंकियों ने एसपीओ को घर में घुसकर गोली मार दी। अस्पताल में उनकी मौत हो गई। कश्मीर में 24 घंटों के अंदर हत्या की यह दूसरी घटना है। इसके बाद घाटी में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है और जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बडगाम में गुरुवार शाम आतंकियों ने चडूरा तहसीलदार ऑफिस के क्लर्क राहुल भट्ट को ऑफिस में घुसकर गोली मार दी। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। आज शुक्रवार को पुलवामा के गुदूरा में आतंकियों ने एसपीओ रियाज अहमद थोकर के घर में घुस गए और उन पर फायरिंग कर दी। अस्पताल में उनकी मौत हो गई।

राहुल भट्ट के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़:- राहुल भट्ट का शुक्रवार सुबह बनतालाब में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जम्मू के ष्ठत्नक्ष मुकेश सिंह, डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं, मौके पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना का लोगों ने विरोध किया। राहुल भट्ट की पत्नी मीनाक्षी ने बताया कि आतंकियों ने ऑफिस में जाकर पूछा राहुल भट्ट कौन है और गोलियां चला दीं। कोई कर्मचारी ही आतंकियों से मिला था, तभी राहुल का नाम आतंकियों को पता था। उन्होंने बताया कि राहुल लगातार ट्रांसफर की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। मीनाक्षी ने सेना से कहा है कि उनके पति के हत्यारों को दो दिन में मार गिराया जाए।

जम्मू-कश्मीर में जगह-जगह प्रदर्शन

इससे पहले गुरुवार रात को जगह-जगह प्रदर्शन किए गए। कश्मीरी पंडितों ने शव के साथ सड़क पर विरोध जताया और उप राज्यपाल के आने तक शव उठाने से इनकार कर दिया। बाद में ष्ठष्ठत्र सुजीत कुमार के आश्वासन पर शव को घर ले जाया गया ।वहीं, बडगाम में शेखपोरा पंडित कॉलोनी के पास कश्मीरी पंडितों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें सुरक्षा का पूरा आश्वासन नहीं मिलता, वो लोग नौकरियों पर नहीं जाएंगे। उधर, कैंप में रह रहे कश्मीरी पंडितों ने हाइवे पर जाम लगाकर केन्द्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

कांग्रेस में अब एक परिवार से एक ही टिकट : गांधी परिवार इस दायरे से बाहर, 5 साल से ज्यादा पद पर नहीं रहेंगे नेता

नई दिल्ली

अगले चुनावों से पहले टिकट दिए जाने को लेकर कांग्रेस बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी कर रही है। अब एक परिवार से केवल एक ही टिकट मिलेगा। उदयपुर में चिंतन शिविर में संगठन में बदलाव और राजनीतिक मामलों पर बने पैनल ने य?ह सिफारिश की है। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी महासचिव अजय माकन ने उदयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा- हमारे पैनल में यह चर्चा हुई है कि एक परिवार से एक टिकट के फार्मूला को लागू किया जाए। जिसे भी टिकट दिया जाए, उसने कम से कम 5 साल पार्टी में काम किया हो। सीधे टिकट नहीं दिया जाए। नए आने वालों नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन इस नियम में गांधी परिवार को छूट दी जाएगी। यह फार्मूला उन पर लागू नहीं होगा।

किसी नेता को तीन साल के कूलिंग पीरियड के बाद दूसरा पद मिले:- माकन ने कहा- इस बात की भी सिफारिश की गई है कि पार्टी में लगातार 5 साल के काम करने के बाद किसी को दूसरा पद नहीं दिया जाए। कम से कम 3 साल का कूलिंग पीरियड रहे। तीन साल के गैप के बाद ही आगे कोई पद दिया जाए।

गांधी परिवार पर लागू नहीं होगा प्रावधान

जब माकन से गांधी परिवार पर यह प्रावधान लागू होने के बारे में पूछा तो कहा कि यह सवाल गांधी परिवार का नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव संगठन चुनाव की प्रक्रिया से होगा। चिंतन शिविर से कांग्रेस अध्यक्ष के चयन का कोई संबंध नहीं है। अजय माकन ने इस तरह के संकेत भी दिए कि गांधी परिवार पर एक परिवार एक टिकट का प्रावधान लागू नहीं होगा। कांग्रेस ने एक परिवार-एक टिकट का फार्मूला लागू करने की सिफारिश की है, लेकिन बड़े सियासी परिवारों के लिए गली भी छोड़ दी है। दरअसल, कांग्रेस नेता के परिवार के किसी दूसरे सदस्य को टिकट तभी दिया जाएगा, जब वह पांच साल से एक्टिव हो, यदि कोई नया सदस्य कांग्रेस में आता है तो उसे पहले 5 साल संगठन में काम करना होगा, उसके बाद ही टिकट मिलेगा। वहीं यह भी तय किया है कि अब पैराशूट उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया जाएगा, उन्हें भी पहले 5 साल संगठन में काम करना पड़ेगा।

सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट:पटना हाईकोर्ट ने 3 राज्यों के डीजीपी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया

नई दिल्ली

इंवेस्टर्स को रुपए नहीं लौटाने के मामले में सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तरप्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने एक दिन पहले सुब्रत राय को कोर्ट में पेश होने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन वे नहीं आए। इस मामले को लेकर अब 16 मई को फिर से सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के सामने वकील ने सुब्रत राय की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। जस्टिस संदीप कुमार ने मेडिकल रिपोर्ट देखकर कहा कि सुब्रत राय को ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि वे कोर्ट नहीं आ सकते।

निवेशकों ने हाईकोर्ट में रुपए लौटाने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका लगाई हुई है। इस मामले में कोर्ट ने 12 मई को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन सुब्रत राय ने अंतरिम आवेदन देकर पेशी से छूट मांगी थी, जिसे कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया था। जस्टिस संदीप कुमार ने आदेश दिया था कि शुक्रवार को हर हाल में सुबह 10~30 बजे सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को हाजिर होना होगा। कल अगर यह फिजिकली नहीं आए तो फिर हाईकार्ट इनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा।

न्यूज ब्रीफ

अकबरुद्दीन की राज ठाकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी : बोले- तुम्हारी औकात नहीं है कि मैं जवाब दूं, जो भौंकता है उसे भौंकने दो

मुंबई। लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति जारी है। इस बीच आग में घी डालने का काम करते हुए AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। अकबरुद्दीन ने औरंगाबाद में आयोजित के सभा में राज ठाकरे का नाम लिए बिना कहा, मैं यहां किसी को जवाब देने आया नहीं हूं, ना ही किसी को बुरा कहने। तुम्हारी औकात नहीं है कि मैं जवाब दूं, मेरा तो एक सांसद है और तुम तो बेघर हो, तुम लापता हो, तुम्हे घर से बेदखल किया गया है। मैं तो यह कहूंगा कि जो भी कुत्ता भौंकता है उसे भौंकने दो। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा, मैं जवाब जरूर देने आऊंगा एक दिन, आम और खास के मैदान पर अकबरुद्दीन ओवैसी लड़ेगा, अपने पसंदीदा जगह और पसंदीदा समय, तुम्हारी पसंदीदा जगह पर नहीं, जगह और समय मैं तय करूंगा। ओवैसी ने आगे कहा मुल्क में नफरत की बातें की जा रही हैं, लेकिन वह नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से जवाब देंगे। देश में अजान की बात हो रही है, लिंचिंग और हिजाब की बात हो रही है, तो डरना नहीं चाहिए बस मुसलमानों को एक साथ इकट्ठा खड़े होने की जरूरत है।

औरंगजेब की कब्र पर भी गए अकबरुद्दीन:- इससे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुलदाबाद में मौजूद औरंगजेब की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाया और इस दौरान उनके साथ औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील और पूर्व विधायक वारिस पठान भी मौजूद थे। विधायक अकबरुद्दीन औवेसी औरंगाबाद में स्कूल ऑफ एक्सिलेंस की नींव रखने आए थे। पूर्व सांसद और शिवसेना नेता चंद्रकांत खैरे ने अकबरुद्दीन पर आरोप लगाया कि वह एक राजनीतिक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

24 घंटे में 2827 नए केस मिले, दिल्ली में सबसे ज्यादा; यूरोप में 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत

नई दिल्ली

देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,827 नए केस सामने आए हैं। ये बुधवार के मुकाबले 2.4 फीसदी कम हैं। वहीं 24 लोगों की मौत हुई, जबकि 2,974 मरीज कोरोना रिकवर हुए। जिसके बाद भारत में कुल रिकवरी रेट 98.74 फीसदी पर पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, डेली पॉजिटिविटी रेट 0.95 फीसदी और वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.82 फीसदी हो गया है। पिछले 24 घंटे में 3,230 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वालों की संख्या 4 करोड़ 25 लाख से ज्यादा पहुंच गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 5 लाख 24 हजार से ज्यादा हो गई है। इधर, डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि यूरोप में कोरोना से 20 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। यूरोप में हुईं सबसे ज्यादा मौतें चिंता का विषय हैं। अभी भी लगातार केस मिल रहे हैं।

अगर यूरोप में सही समय में इन आंकड़ों को नहीं रोका गया तो इनकी संख्या में अभी और बढ़ोत्तरी होगी।

दिल्ली में रोज आ रहे सबसे ज्यादा मामले:- हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में गुरुवार को 1,032 नए केस मिले हैं। इसके बाद पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 3.64 फीसदी हो गई। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 28,386 टेस्ट किए गए थे। बुधवार को राज्य में 970 केस और एक मौत दर्ज दी गई थी, जबकि पॉजिटिविटी रेट 3.34 फीसदी थी। मध्यप्रदेश में गुरुवार को कोरोना के 40 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल केस 10 लाख 41 हजार से ज्यादा हो गए हैं। राज्य में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है, जिसकी वजह से कोरोना से मरने वालों की संख्या 10,735 पर ही बनी हुई है। पॉजिटिविटी रेट प्रति 100 टेस्ट के हिसाब से 0.50 फीसदी है। राज्य में कोरोना के 8000 टेस्ट किए गए। वहीं हरियाणा में 354 नए मामले मिले हैं, जबकि एक भी मौत नहीं हुई है। राज्य में कोरोना एक्टिव केस 1930 हैं और कुल मामले 99 लाख से ज्यादा हो गए हैं। राज्य में गुरुवार को 13,653 टेस्ट किए गए। महाराष्ट्र में 28,191 टेस्ट किए गए, जिसमें 231 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 0.82 फीसदी रहा है। कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 208 रही है। राज्य में कोरोना से आज 1 व्यक्ति की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मरने वालों की संख्या 1,47,851 हो गई है।

नॉर्थ कोरिया में कोरोना से पहली मौत

लगभग 2 लाख लोग आइसोलेट, किम के आदेश पर देश में लगा सख्त लॉकडाउन

प्योंगयांग

नॉर्थ कोरिया में कोरोना का पहला केस मिलने के बाद शुक्रवार को एक मरीज की मौत हो गई। वहीं, 5 ऐसे लोगों की भी जान गई है जिनमें कोरोना की पुष्टि नहीं हुई थी। सरकारी मीडिया के मुताबिक फिलहाल देश में 1,87,000 लोगों को बुखार के लक्षण आ रहे हैं, जिस कारण उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। बता दें कि नॉर्थ कोरिया में 8 मई को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। गुरुवार को इसकी पुष्टि की गई और इसके साथ ही पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक, नॉर्थ कोरिया ने 2020 के आखिर तक 13,259 लोगों के सैंपल्स की जांच की थी। इनमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई।

नॉर्थ कोरिया में फैल रहा बुखार:- देश की चष्टद्व न्यूज एजेंसी के अनुसार, राजधानी प्योंगयांग में अप्रैल के आखिर में अचानक से लोग बुखार की चपेट में आने लगे। ये बुखार फैलते-फैलते प्योंगयांग के बाहर जा पहुंचा। अब तक कुल 3,50,000 लोगों में इस बुखार के लक्षण देखे गए हैं। हालांकि, इनमें से कितने लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, एजेंसी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है।

देश में कोई भी वैक्सीनेटेड नहीं

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, नॉर्थ कोरिया इस वक्त कोरोना विस्फोट की स्थिति में हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश में रहने वाले 2.5 करोड़ लोग खतरे में हैं, क्योंकि यहां न तो किसी को वैक्सीन लगेगी, न ही अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। यहां फैल रहा बुखार असल में कोरोना का ओमिक्रॉन वैरिएंट हो सकता है। दरअसल, नॉर्थ कोरिया ने ब्रिटेन और चीन जैसे देशों में बनी वैक्सीन खरीदने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बजाय सरकार का कहना था कि उसने जनवरी 2020 में सभी बॉर्डर्स बंद कर कोरोना को देश के अंदर आने से रोक दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ कोरिया के लिए असली खतरा कोरोना नहीं, बल्कि लॉकडाउन है। आबादी का बड़ा हिस्सा वैसे ही कुपोषण का शिकार है।

PRESS ITDC ITDC NEWS
www.itdcindia.com

मध्य भारत से विश्वसनीय हिन्दी दैनिक समाचारपत्र
आईटीडीसी न्यूज़,

विश्वसनीयता की अपेक्षा पर सच्चा बनाने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं,
प्रति सप्ताह आप सभी का स्तम्भ

मेरे लोग, मेरा विधान

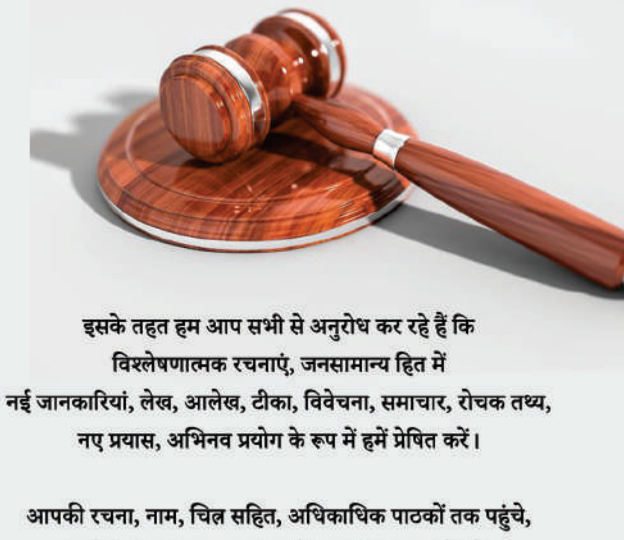

इसके तहत हम आप सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि
विश्लेषणात्मक रचनाएं, जनसामान्य हित में
नई जानकारियां, लेख, आलेख, टीका, विवेचना, समाचार, रोचक तथ्य,
नए प्रयास, अभिनव प्रयोग के रूप में हमें प्रेषित करें।

आपकी रचना, नाम, चित्र सहित, अधिकाधिक पाठकों तक पहुंचे,
इसके लिए हम, समाचार पत्र में प्रकाशित रचनाओं को,
देश के सभी प्रचलित सोशल मीडिया स्टैंड जैसे फेसबुक, लिंकेडीन, यूट्यूब, जीटॉक, टिवीटर, इंस्टाग्राम
व्हाट्सएप्प एवं हमारे डिजिटल स्टैंड से प्रचार-प्रसार भी देंगे।
(दीर्घ समय तक https://www.itdcindia.com/saga-news.php पर भी उपलब्ध)
जिससे लाभान्वित जनों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे।

आप सभी इच्छुकजन अपनी गैरमानदेय,
अपठित, नवीन, मूल एवं मौलिक रचना, हिन्दी में हमें प्रेषित करें।
(और अंग्रेजी में भेजने पर केवल हमारे डिजिटल स्टैंड पर ही प्रकाशन होगा)
उक्त हेतु, आपका चित्र, नाम, शहर, मोबाइल न, आपकी रचना, मेल करें-ईमेल
itdcnewsmp@gmail.com

मध्य भारत का विश्वसनीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
इंटीग्रेटेड ट्रेड डेव्हेलपमेंट सेंटर न्यूज़

न्यूज़ ब्रीफ

कुल्हे की चोट के चलते आईपीएल से बाहर हुए पैट कमिंस

मुंबई। कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज़ गेंदबाज़ पैट कमिंस कुल्हे की चोट के कारण आईपीएल 2022 से बाहर हो गए हैं। माना जा रहा है कि वह अपने घर सिडनी के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर वह इस चोट से उबर कर अगले महीने होने वाले श्रीलंका दौरे की तैयारी करेंगे। कमिंस ने इस सीज़न में पांच मैच खेले। मुंबई इंडियंस के ख़िलाफ़ उन्होंने रिकॉर्ड पारी खेली और टूर्नामेंट का सबसे तेज़ अर्धशतक लगाया। मुंबई इंडियंस के ख़िलाफ़ ही दूसरे मैच में उन्होंने 22 रन देकर तीन विकेट लिए जो इस सीज़न की उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी रही। कुल मिलाकर उन्होंने इस साल पांच मैचों में सात विकेट लिए। गेंदबाज़ी प्रदर्शन में निरंतर उतार-चढ़ाव के कारण उन्हें टीम से अंदर-बाहर होना पड़ा। अब जबकि कोलकाता के प्लेऑफ़ में पहुंचने की संभावना लगभग क्षीण हो चुकी है और ऑस्ट्रेलिया को इस साल काफ़ी क्रिकेट खेलना है, इसे देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान ने घर-वापसी का निर्णय लिया है। कमिंस श्रीलंका दौरे पर टी20 मुक़ाबले नहीं खेलेंगे, उन्हें आराम दिया गया है। लेकिन इसके बाद उन्हें श्रीलंका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़, घर पर पांच टेस्ट मैच, भारत का दौरा और फिर साल के अंत में इंग्लैंड जाकर ऐशेज़ खेलना है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में ही टी20 विश्व कप होगा, जहां पूरी संभावना है कि वह टीम का हिस्सा होंगे।

कोरोना मुक्त हुए शाकिब अल हसन

कोलंबो। श्रीलंका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ से पहले बांग्लादेश टीम ने राहत की सांस ली है क्योंकि उनके स्टार हरफ़नमौला शाकिब अल हसन कोरोना मुक्त हो चुके हैं। मंगलवार को शाकिब आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉज़िटिव पाए गए थे। बांग्लादेशी टीम के एक अधिकारी ने बताया कि शाकिब शुक्रवाल को चटगांव पहुंचेंगे जहां उन्हें मेडिकल और फ़िटनेस टेस्ट से गुज़रना होगा। इसके बाद ही टीम में उन्हें शामिल करने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। शाकिब 11 मई को टेस्ट दल के साथ जुड़ने वाले थे। हालांकि कोरोना संक्रमित होने के कारण उन्हें क्वारंटीन में रहना पड़ा। बांग्लादेश ने उनके बदले किसी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी की घोषणा नहीं की थी और शाकिब का वापस आना चोट से ग्रस्त टीम के लिए ख़ुशी की लहर से कम नहीं है। मेहदी हसन मिराज़ और तस्कीन अहमद क्रमश: उंगली और कंधे की चोट के चलते पहले ही टीम से बाहर हैं, जबकि टीम में चुने जाने के बावजूद शोरिफ़ुल इस्लाम की फ़िटनेस पर संदेह बना हुआ है। गेंदबाज़ी के साथ-साथ बांग्लादेश की बल्लेबाज़ी को भी मध्य क्रम में शाकिब के अनुभव की आवश्यकता है। साउथ अफ़्रीका में दो मैचों में लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेशी टीम 53 और 80 के स्कोर पर सिमट गई थी। शाकिब की जगह को भरने के लिए टीम को दो खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ रही थी। हालांकि अब उनके टीम में आने के बाद बांग्लादेश घर पर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप वाली इस सीरीज़ में श्रीलंका के ख़िलाफ़ बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी।

चेन्नई को डीआरएस ने डुबोया : गलत फैसले का शिकार हुए चेन्नई के ओपनर कॉनवे, टेक्निकल फॉल्ट के कारण डीआरएस ही नहीं ले सके

नई दिल्ली

टेक्निकल फॉल्ट किसी मुकाबले का रुख बदल सकता है, इसका नजारा मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले में देखने को मिला। मैच के पहले ही ओवर में डेनियल सैम्स ने डेवॉन कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट किया। चेन्नई की पारी की दूसरी गेंद कॉनवे के पैर पर लगी और अंपायर ने तुरंत उंगली ऊपर कर दी। कॉनवे रिव्यू लेना चाहते थे लेकिन, टेक्निकल फॉल्ट के कारण डीआरएस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। रिप्ले से लग रहा था कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। ऐसे में डीआरएस का न होना चेन्नई को बहुत भारी पड़ा। नॉन-स्ट्राइक पर खड़े ऋतुराज गायकवाड़ भी विवाद में कूद पड़े। ऋतुराज ने साफ तौर पर गेंद की लाइन देखी थी और उन्हें पूरा यकीन था कि कॉन्वे आउट नहीं हैं। आउट होकर धीमे कदमों से पवेलियन लौटने के दौरान कॉनवे के चेहरे पर बेबसी साफ देखी जा सकती थी। सैम्स ने इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर मोइन अली (0) को भी आउट कर दिया।

उपलब्ध हो सका डीआरएस

दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने रॉबिन उथप्पा को एलबीडब्ल्यू आउट किया। इस वक्त भी डीआरएस उपलब्ध नहीं था। हालांकि, पहली नजर में उथप्पा आउट नजर आ रहे थे। डीआरएस होता तो उथप्पा भी डिसीजन का रिव्यू ले सकते थे। इसके कुछ देर बाद डीआरएस उपलब्ध हो गया। सैम्स ने अपने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर गायकवाड़ को विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच कराया। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह मुकाबला बेहद जरूरी था। अगर वह जीतती तो कम से कम आगे बढ़ने की उम्मीद जीवित रहती। ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के दौरान पावर कट की वजह से डीआरएस का उपलब्ध ना होना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। टूर्नामेंट में लगातार 3 अर्धशतक जड़ चुके डेवॉन कॉनवे के विकेट के बाद चेन्नई संभल नहीं पाई। सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर काफी रिएक्शन सामने आ रहे हैं।

चेन्नई प्लेऑफ की रेस से बाहर

मुकाबले के दिन कीरोन पोलार्ड का जन्मदिन भी था। ऐसे में कुछ मीम्स वायरल हुए, जिनमें उन्हें पावर कनेक्शन कट करते हुए दिखाया गया। दरअसल पोलार्ड को खराब फॉर्म के कारण टीम में नहीं चुना गया था। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2022 में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की टीम 16 ओवर में 97 रन के स्कोर पर ऑलआउट हो गई। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे ज्यादा नाबाद 36 रन बनाए। डेनियल सैम्स ने 3 विकेट लिए। जवाब में मुंबई ने शुरुआत में लड़खड़ाने के बाद आखिरकार 14.5 ओवर में 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। 98 रन के टारगेट के जवाब में मुंबई ने 33 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद तिलक वर्मा और ऋतिक शौकीन ने पांचवें विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी कर मुंबई की वापसी करा दी। ऋतिक 18 रन बनाकर आउट हुए। तिलक 34 रन बनाकर नाबाद रहे। टिम डेविड 7 गेंदों पर 16 रन बनाकर नाबाद रहे।

नई गेंद के साथ मुकेश और सिमरजीत ने कमाल की गेंदबाज़ी की : फ़्लेमिंग

नई दिल्ली

मुंबई इंडियंस के विरुद्ध मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए कभी भी 100 से कम के स्कोर पर ऑल आउट नहीं हुई थी। हालांकि हर सिलसिले को एक न एक दिन अपने अंजाम तक पहुंचना पड़ता है और वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई की टीम तेज़ गेंदबाज़ी के लिए मददगार पिच पर सिर्फ़ 97 रनों पर सिमट गई। पांच विकेट और 31 गेंद शेष रहते चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा लेकिन इस मैच में उनके दृष्टिकोण से कई सकारात्मक पहलू रहे। मुकेश चौधरी और सिमरजीत सिंह की तेज़ गेंदबाज़ी जोड़ी ने लगातार आठ ओवर डाले और एक समय मुंबई को चार विकेट के नुक़सान पर 33 रन की स्थिति पर ला खड़ा कर दिया। मुकेश ने 23 रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए जबकि सिमरजीत ने विपक्षी कप्तान रोहित शर्मा के रूप में बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मैच के बाद ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत के दौरान अपने दो शेरों की प्रशंसा की।

धोनी ने कहा, किसी भी प्रकार की विकेट पर 130 से कम के लक्ष्य का बचाव करना बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद मैंने गेंदबाज़ों से नतीजे की परवाह किए बिना जज़्बा दिखाने और विपक्षी टीम पर दबाव बनाने को कहा। मुझे लगता है कि दोनों युवा तेज़ गेंदबाज़ों ने बढ़िया गेंदबाज़ी की। ऐसे मैच से उन्हें बहुत आत्मविश्वास मिलेगा। वह इस मानसिकता के साथ उतरेंगे कि परिस्थितियां चाहे जो भी हो, हमें इसी जज़्बे के साथ सबसे छोटे प्रारूप को खेलना होगा। आईपीएल 2022 जीतने की चेन्नई की उम्मीदों को सीज़न से पहले ही बड़ा झटका लगा था, जब 14 करोड़ देकर टीम में शामिल किए गए दीपक चाहर पीठ में लगी चोट के चलते सीज़न से बाहर हो गए थे। अगले साल चेन्नई के पास दीपक, मुकेश और सिमरजीत की तेज़ गेंदबाज़ी तिकड़ी को एक साथ मैदान पर उतारने का मौक़ा होगा और कोच स्टीफ़न फ़्लेमिंग इस बात से काफ़ी उत्साहित हैं। मैच के बाद पत्रकार-वार्ता में फ़्लेमिंग ने कहा, मुझे लगा कि नई गेंद के साथ मुकेश और सिमरजीत ने शानदार गेंदबाज़ी की। इस पूरे सीज़न में उनका विकास हो रहा है। मुकेश के लिए आत्मविश्वास के साथ ऐसा स्पेल डालना और तीन-चार मैच खेलने वाले सिमरजीत के लिए अच्छा करना बहुत बड़ी बात है। दीपक चाहर के टीम में लौटने के बाद हमारे पास नई गेंद के साथ कुछ बढ़िया विकल्प होंगे। विशेष रूप से फ़्लेमिंग प्रसन्न थे कि मुकेश और सिमरजीत ने मुश्किल स्थिति में नई गेंद के साथ कमाल किया था। उन्होंने कहा, मुकेश ने गेंद को लहराया जबकि सिमरजीत के पास घातक गति है। हम भविष्य में इस जोड़ी को लेकर सकारात्मक है। निराशा बस इस बात की है कि हमारे पास पर्याप्त रन नहीं थे। इसके बावजूद इन दोनों ने कमाल किया। मुकेश और सिमरजीत युवा तेज़ गेंदबाज़ों की उस सूची का हिस्सा हैं, जिन्होंने इस सीज़न में अपनी छाप छोड़ी हैं। उमरान मलिक, मोहसिन ख़ान, यश दयाल, कुलदीप सेन और अर्शदीप सिंह ने सुर्ख़ियां बटोरी हैं।

धोनी तेज़ गेंदबाज़ों की नई पीढ़ी के आने से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, 卐हम उस दौर से भी गुज़रे हैं जहां टीम के पास तेज़ गेंदबाज़ों का बड़ा समूह नहीं होता था। तेज़ गेंदबाज़ों को परिपक्व होने में समय लगता है। आईपीएल इन युवा गेंदबाज़ों को निडर होकर खेलने का अवसर देता है। जैसे-जैसे वह अधिक मैच खेलते हैं, उन्हें आत्मविश्वास मिलता है और वह मैदान पर अपनी योजनाओं पर अमल करते हैं।

भारत के लिए जल्द ही तीनों फ़ॉर्मेट खेलेंगे तिलकः रोहित

मुंबई

मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा मध्य क्रम के बाएं हाथ के बल्लेबाज़ तिलक वर्मा से बहुत प्रभावित हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि वह जल्द ही भारत के लिए तीनों फ़ॉर्मेट खेलेंगे। रोहित ने कहा कि उनमें तकनीक और मानसिकता दोनों है और वह बेहद शांत दिमाग़ से मैदान में उतरते हैं। तिलक ने भारत के लिए 2020 में अंडर-19 विश्व कप खेला था, जिसमें भारत उपविजेता रहा था। उन्हें 2022 में मुंबई इंडियंस ने ख़रीदा और उन्होंने अपने पहले ही आईपीएल सीज़न में कमाल कर दिया। टीम के ख़राब प्रदर्शन के बीच 19 साल के तिलक ने अब तक 12 पारियों में 386 रन बना लिए हैं, जो कि किसी भी 20 साल से कम के बल्लेबाज़ का सर्वश्रेष्ठ आईपीएल प्रदर्शन है। उन्होंने ऋषभ पंत के रिकॉर्ड को तोड़ा, जिन्होंने 2017 में 366 रन बनाए थे। वर्तमान में तिलक इस सीज़न में सातवें सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स पर मिली जीत के बाद रोहित ने तिलक की भूरी-भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, 卐पहले ही साल में वह जो कर रहे हैं, वह कमाल है। इस उम्र में ही उन्होंने मानसिकता दिखाई है और बेहद शांत दिमाग़ से क्रिकेट खेला है। मुझे लगता है कि वह जल्द ही भारत के लिए तीनों फ़ॉर्मेट खेलेंगे। जब आप उनसे बात करो तो पता चलता है कि उनमें कुछ अच्छा करने और सफलता पाने की भूख है। वह सही रास्ते पर हैं, उन्हें बस इसी रास्ते पर चलते जाना है। रोहित ने कहा कि उनकी टीम भले ही इस सीज़न बाहर हो गई है, लेकिन अब वह बाक़ी बचे मैचों में भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में चेन्नई के ख़िलाफ़ हुए मैच में साउथ अफ़्रीका के युवा खिलाड़ी ट्रिस्टन स्टब्स को मौक़ा दिया गया। रोहित ने कहा, 卐हमारी नज़र निश्चित रूप से भविष्य पर है, लेकिन हम जीत के साथ टूर्नामेंट समाप्त करना चाहते हैं।

डीआरएस प्रकरण पर फ़्लेमिंग : हम थोड़े निराश थे लेकिन यह खेल का हिस्सा है

मुंबई।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2022 के 59वें मैच की शुरुआत थोड़ी अजीबोगरीब रही। वानखेड़े स्टेडियम में बिजली गुल होने के कारण पहले दो ओवरों में डीआरएस प्रणाली अनुपलब्ध थी। इस अनुपलब्धता को मैच को प्रभावित करने में केवल दो गेंदें लगी। डेनियल सैम्स की गेंद पर पगबाधा करार दिए जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज़ डेवन कॉन्वे को रिव्यू लिए बिना ही पवेलियन लौटना पड़ा। रिप्ले में पता चला कि वह गेंद कोण के साथ अंदर आ रही थी और बाएं हाथ के बल्लेबाज़ कॉन्वे के लेग स्टंप को मिस करती। हालांकि अंपायर रविकांत रेड्डी के फ़ैसले की दोबारा जांच करने का कोई मौक़ा नहीं था। अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंदबाज़ी पर एक और फ़ैसला मुंबई के हित में गया जब उनकी गुड लेंथ की गेंद पड़कर सीधी हुई और रॉबिन उथप्पा के पैड पर जा लगी। इस बार अंपायर क्रिस गैफ़ने ने अपनी उंगली खड़ी कर दी। रिप्ले ने बताया कि यह एक क़रीबी मामला होता क्योंकि गेंद उथप्पा के पिछले पैर पर लगी थी और वह भी ऑफ़ स्टंप के सामने। हालांकि यहां पर भी रिव्यू नहीं होने के कारण उथप्पा को निराश होकर वापस जाना पड़ा। 97 रनों पर सिमटने के बाद चेन्नई को पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद उनके प्रमुख कोच स्टीफ़न फ़्लेमिंग इस पूरे प्रकरण को लेकर दार्शनिक थे। फ़्लेमिंग ने कहा, जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था। हम थोड़े निराश थे लेकिन यह खेल का हिस्सा है। वहां से विकेटों की एक झड़ी सी लग गई, जहां सब कुछ हमारे ख़िलाफ़ जाने लगा। लेकिन हमें 97 ऑल आउट से बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था।

इंग्लैंड की टेस्ट टीम को फ़र्श से उठाना असली चुनौती : मक्कलम

लंदन

इंग्लैंड के नए टेस्ट कोच ब्रेंडन मक्कलम ने कहा है कि सफ़ेद गेंद टीमों को संभालने के आरामदेय काम से इतर उन्होंने इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट को फ़र्श से उभारने की जिम्मेदारी को पसंद किया। मक्कलम के नियुक्ति की घोषणा गुरुवार को की गई और वह कोलकाता नाइट राइडर्स के आईपीएल अभियान की समाप्ति के तुरंत बाद न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 2 जून से होने वाली सीरीज़ से पहले टीम के साथ जुड़ जाएंगे। एसईएनज़ेड रेडियो से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैंने दोनों भूमिकाओं को देखा लेकिन सफ़ेद गेंद के कोच की भूमिका मुझे रास नहीं आई। इन प्रारूपों में इंग्लैंड शायद दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम है और वहां मेरे अच्छे दोस्त ओएन मॉर्गन ने बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया है, जो मुझे लगता है कि उनके बाद भी अच्छे से चलती रहेगी। मेरे लिए ऐसी आरामदेय काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे हमेशा लगता है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा संघर्षपूर्ण चुनौती की ज़रूरत होती है। फ़िलहाल इंग्लैंड की [टेस्ट] टीम फ़र्श पर है और इसे आने वाले वक़्त में एक सफल टीम बनाने में ही असली चुनौती दिखी। मक्कलम ने यह भी माना कि अपने पिछले 17 में सिर्फ़ एक टेस्ट जीते हुए इंग्लैंड को सशक्त बनाना टेस्ट फ़ॉर्मेट के स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। मक्कलम का अनुबंध चार साल का है अर्थात वह 2025-26 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले ऐशेज़ तक टीम के साथ होंगे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता दिन पे दिन कम हो रही है। मैं सीमित ओवर की क्रिकेट और फ़्रैंचाइज़ी क्रिकेट के साथ जुड़े रहने में काफ़ी भाग्यशाली रहा हूं, लेकिन मेरा असली प्यार टेस्ट क्रिकेट ही है। अगर टेस्ट क्रिकेट को कोई देश फिर से आकर्षक और लोकप्रिय बना सकता है तो वह इंग्लैंड ही है। अगर आप चहरे पर मुस्कान लिए एक आकर्षक टेस्ट शैली खेल सकते हैं तो ऐसे में मुझे लगा कि अगर मुझे इस काम के क़ाबिल समझा गया है तो यह मेरे लिए सही है।

मक्कलम बेन स्टोक्स की कप्तानी को क़रीब से देखने के बारे में भी उत्साहित हैं। न्यूज़ीलैंड में जन्में स्टोक्स और अपने हमवतन होने के बारे में मज़ाक़ करने के बाद वह बोले, जिस प्रकार स्टोक्स अपना क्रिकेट खेलते हैं वह मेरे खेल और कोचिंग शैली से काफ़ी मिलता है। वह स्वच्छंद रूप से विपक्ष पर दबाव डालते हैं। हालांकि लॉर्ड्स टेस्ट का पहला दिन काफ़ी रोचक होगा। लेकिन मज़ा भी आने वाला है।

SUPER HERO

यदि आप

किसी भी व्यक्ति को जानते हैं
जिसने, सामाजिक सरोकार में
असाधारण प्रदर्शन किया हो,
वह व्यक्ति आप स्वयं भी हो सकते हैं,
दोनों स्थिति में हमें पूर्ण विवरण, भेजें।

हम देश के असली नायक
SUPER HERO MP 2021
SUPER HERO IND 2021
खोज रहें हैं, उन्हें समाज, राष्ट्र के सामने लाना और
सम्मान दिलवाना, आपका-हमारा सयुंक्त प्रयास रहेगा।

Contact: Editorial Desk (Lifestyle), ITDC News, 9826 220022
Email: responseitdc@gmail.com

PRESS ITDC
ITDC NEWS
www.itdcindia.com

न्यूज ब्रीफ

एअर इंडिया को मिला नया सीईओ : 50 साल के विल्सन संभालेंगे एअर इंडिया की जिम्मेदारी

नई दिल्ली। टाटा संस ने कैंपबेल विल्सन को एअर इंडिया का नया एमडी और सीईओ बनाया है। एअर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस नियुक्ति पर कहा, अर इंडिया में कैंपबेल का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। वह इंडस्ट्री के दिग्गज हैं। एअर इंडिया को अनुभव से फायदा मिलेगा। मैं वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनाने में उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।

50 साल के विल्सन के पास एविएशन इंडस्ट्री का 26 साल का अनुभव है। इसमें फुल सर्विस और लो-कॉस्ट दोनों एयरलाइन्स शामिल है। उन्होंने सिंगापुर एयरलाइंस ग्रुप के लिए जापान, कनाडा और हॉन्गकॉन्ग जैसे देशों में 15 से अधिक वर्षों तक काम किया है। यहां हम आपको ये भी बता दें कि टाटा के स्वामित्व वाली एयरलाइन विस्तारा में SIA भी पार्टनर है।

टाटा ग्रुप का हिस्सा बनना सम्मान की बात

कैंपबेल विल्सन ने कहा, आईकॉनिक एअर इंडिया का नेतृत्व करने और टाटा ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए चुना जाना एक सम्मान की बात है। एअर इंडिया दुनिया की बेस्ट एयरलाइन्स में से एक बनने की रोमांचक यात्रा पर है। मैं उस महत्वाकांक्षा को साकार करने के मिशन में एअर इंडिया और टाटा के सहयोगियों के साथ जुड़ने के लिए उत्साहित हूं।

विल्सन ने 1996 में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में शुरुआत की थी

विल्सन ने न्यूजीलैंड में कैंटरबरी यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर ऑफ कॉमर्स किया है। उन्होंने 1996 में न्यूजीलैंड में सिंगापुर एयरलाइन्स के साथ मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कनाडा, हॉन्ग कॉन्ग और जापान में SIA के लिए काम किया।

2011 में स्कूट के फाउंडिंग सीईओ बने थे विल्सन

सिंगापुर लौटकर 2011 में लो कॉस्ट एयरलाइन स्कूट के फाउंडिंग सीईओ के रूप में काम किया। 2016 तक वो इस पद पर रहे। अप्रैल 2020 में दोबारा स्कूट के सीईओ बनने से पहले उन्होंने SIA में सेल्स और मार्केटिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने प्राइसिंग, डिस्ट्रिब्यूशन, ई-कॉमर्स, मर्चेंडाइजिंग, ब्रांड एंड मार्केटिंग, ग्लोबल सेल्स और एयरलाइन ओवरसीज ऑफिसेज को देखा। अब उन्हें एअर इंडिया की कमान सौंपी गई है। उम्मीद की जा रही है कि स्कूट एयरलाइन का उनका एक्सपीरिएंस एअर इंडिया के काफी काम आएगा।

इल्कर आयसी ने ठुकराया था सीईओ का पद

टाटा ने इससे पहले तुर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर आयसी को एमडी और सीईओ नियुक्त किया था, लेकिन बाद में उन्होंने एयरलाइन की कमान संभालने से इनकार कर दिया।

कंपनियों का महंगाई से निपटने का प्लान : सामान की कीमत नहीं बढ़ाई लेकिन वजन घटाया, 155 ग्राम वाला विम बार 135 ग्राम का हुआ

नई दिल्ली

देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। खाने पीने के सामान से लेकर कपड़े और जुते तक लेना महंगा हो गया है। अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 8 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर 7.79 फीसदी हो गई है। लेकिन महंगाई की बढ़ने के बावजूद साबुन और कुकीज जैसे स्टेपल के सस्ते सिंगल-सर्विंग पैकेट की कीमत नहीं बढ़ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनियां इनका रेट बढ़ाने के बजाया पैकेट का वजन घटा रही है। यानी उतने ही रुपए में कम सामान दे रही है। अर्थशास्त्र में इस तरह बढ़ने वाली महंगाई को अंग्रेजी में श्रृंकफ्लेशन और हिंदी में सिकुड़न कहते हैं। इसमें प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाने के बजाए क्वांटिटी कम कर दी जाती है।

कीमत स्टेबल रखकर मात्रा घटाई

एडिबल ऑइल, अनाज और फ्यूल की बढ़ती कीमतों के बीच यूनिलीवर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और डाबर इंडिया लिमिटेड सहित अन्य कंपनियों ने अपने पैकेट्स की कीमत को स्टेबल रखकर उंदर रखे सामान की मात्रा को घटा दिया है। ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है। सबवे और डोमिनोज सहित अमेरिका की कई कंपनियों ने लागत कम करने के लिए सामान की मात्रा को कम किया है।

विम बार 155 ग्राम से घटकर 135 हुआ

बीते दिनों चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करते हुए हिंदुस्तान यूनिलीवर के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रितेश तिवारी ने कहा था, अगली दो से तीन तिमाहियों में महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए कुछ पैक्स में वॉल्यूम कमा करना ही एक तरीका है। उदाहरण के लिए कंपनी का बर्तन धोने में इस्तेमाल होने वाला पॉपुलर प्रोडक्ट विम बार 10 रुपए में 155 ग्राम मिलता था। इसका वजन घटाकर 135 ग्राम कर दिया गया है। इसी तरह हल्दीराम का आलू भुजिया के पैक का वजन 55 ग्राम से घटकर 42 ग्राम हो गया है। तिवारी ने कहा कि एक और नई रणनीति जो कंपनियां अपना रही है वो है ब्रिज पैक। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने 10 और 35 रुपए के लाइफबॉय साबुन के बीच एक नए साइज का पैक पेश किया है। पारले-जी बिस्किट की कीमत फरवरी में भी 5 रुपए थी और अब भी 5 रुपए ही है, लेकिन वजन 64 ग्राम से घटाकर 55 ग्राम कर दिया।

लगातार चौथे महीने महंगाई RBI की लिमिट के पार

अप्रैल में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 7.79 फीसदी पर पहुंच गई। यह लगातार चौथा महीना है, जब महंगाई दर RBI की 6 फीसदी की ऊपरी लिमिट के पार रही है। फरवरी 2022 में रिटेल महंगाई दर 6.07 फीसदी, जनवरी में 6.01 फीसदी और मार्च में 6.95 फीसदी दर्ज की गई थी। एक साल पहले अप्रैल 2021 में रिटेल महंगाई दर 4.23 फीसदी थी।

खुदरा महंगाई 95 माह में सर्वाधिक

नई दिल्ली

देश में खुदरा महंगाई अप्रैल में बढ़कर 7.8 फीसदी पर पहुंच गई, जो 95 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे केंद्रीय बैंक के नीतिगत दरों में और बढ़ोतरी करने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि फैक्टरी उत्पादन की वृद्धि मार्च में 1.9 फीसदी के कमजोर स्तर पर रही, जिससे कमजोर घरेलू मांग का पता चलता है। खुदरा महंगाई में अनुमान से अधिक तेजी ने पिछले सप्ताह दर में 40 आधार अंक की बढ़ोतरी के भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आकस्मिक निर्णय को सही ठहराया है। महंगाई लगातार चार महीनों से केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित दायरे की ऊपरी सीमा से अधिक बनी हुई है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल में खाद्य महंगाई बढ़कर 8.38 फीसदी रही। इसकी मुख्य वजह खाद्य तेल की कीमतों में 17.3 फीसदी और सब्जियों की कीमतों में 15.4 फीसदी बढ़ोतरी रही। ईंधन की महंगाई भी अप्रैल में दो अंकों को पार 10.8 फीसदी रही क्योंकि मार्च से कच्चे तेल की कीमतें नरम पडने् के बावजूद पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की खुदरा कीमतें बढ़ रही हैं। ऊर्जा की कीमतों के दूसरे चरण का असर साफ नजर आने लगा है। परिवहन और संचार कीमतों में अप्रैल में बढ़ोतरी दो अंकों में 10.9 फीसदी रही। पूरे सेवा क्षेत्र की महंगाई 115 महीनों के सर्वोच्च स्तर 8.03 फीसदी पर पहुंच गई क्योंकि घरेलू सामान एवं सेवाओं (7.79 फीसदी) तथा पर्सनल केयर (8.62 फीसदी) में अप्रैल के दौरान बढ़ोतरी हुई है।

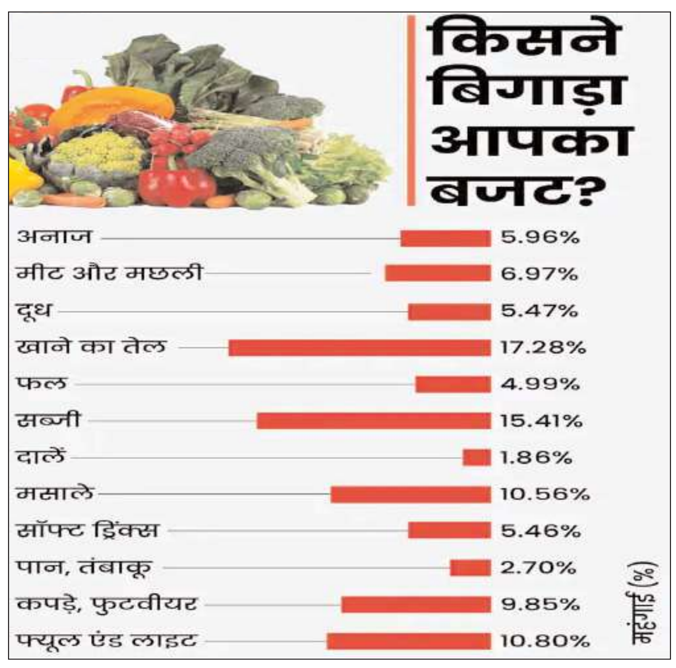

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज में वरिष्ठ अर्थशास्त्री शुभदीप रक्षित ने कहा कि भले ही अप्रैल में मुख्य महंगाई के आंकड़े वर्ष के सबसे ऊंचे स्तर पर रहे हों, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि महंगाई साल की बाकी अवधि में 6 फीसदी से नीचे आएगी और आगामी कुछ महीनों में आंकड़े 7 से 7.5 फीसदी के बीच रहेंगे। उन्होंने कहा, %हमें महंगाई की चाल का पता लगाने के लिए अगले कुछ महीनों के दौरान खाद्य तेलों, कच्चे तेल की कीमतों, ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी, खरीफ एमएसपी घोषणा और कंपनियों के इनपुट लागत का बोझ ग्राहकों पर डाले जाने पर ध्यान देना होगा।%

उद्योग सुस्त

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का कमजोर प्रदर्शन मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र की वजह से रहा, जिसमें महज 0.9 फीसदी की वृद्धि रही। इसके अलावा खनन क्षेत्र में 4 फीसदी और बिजली क्षेत्र में 6.1 फीसदी वृद्धि रही। पूंजीगत वस्तुओं (0.7 फीसदी) में वृद्धि कमजोर रही, जबकि बुनियादी ढांचा वस्तुओं में वृद्धि 7.3 फीसदी के शानदार स्तर पर रही। हालांकि टिकाऊ उपभोक्ता सामान के उत्पादन में लगातार छठे महीने कमी (-3.2 फीसदी) आई और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ क्षेत्र में लगातार दूसरे महीने गिरावट (-5 फीसदी) रही। इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च में मुख्य अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि आईआईपी वृद्धि के तरीके से संकेत मिलता है कि आगे उपभोक्ता मांग को ऊंची महंगाई और ब्याज दरों में तेजी का दौर लौटने की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सरकार के लगातार पूंजीगत खर्च जारी रखने से बुनियादी ढांचा वस्तुओं की मांग बनी रह सकती है। ईवाई इंडिया में मुख्य नीति सलाहकार डी के श्रीवास्तव ने कहा कि महंगाई के रुझान को देखते हुए आरबीआई एक या दो बार में नीतिगत दर 50 आधार अंक बढ़ाने के बारे में विचार कर सकता है।

वेतन बढ़ोतरी कोविड से पहले के स्तर पर पहुंची

नई दिल्ली

वेतन में औसत वृद्धि वित्त वर्ष 2022 में लगभग 8.13 प्रतिशत रही है और यह कोविड के पहले के स्तर के करीब पहुंच रहा है। एक प्रमुख कंपनी टीमलीज सर्विसेज इंडिया की नौकरियों और वेतन से जुड़े प्राइमर रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण में ऐसा रुझान देखने को मिला है। पिछले संस्करण के दौरान यह औसत वृद्धि लगभग 7.12 प्रतिशत थी। रिपोर्ट के अनुसार, जिन 17 क्षेत्रों की समीक्षा की गई है उनमें से 14 ने एकल अंकों की वृद्धि का संकेत दिया है जबकि ई-कॉमर्स और तकनीकी स्टार्टअप, स्वास्थ्य देखभाल और संबद्ध उद्योग तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और ज्ञान सेवाएं केवल तीन ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें 10 प्रतिशत से अधिक वेतन वृद्धि दर्ज की जाती है। आठ फंक्शन, 263,000 अस्थायी प्रोफाइल, 17 उद्योगों और 9 शहरों में नौकरियों और भुगतान के रुझानों को कवर करने के लिए किए गए गहन शोध पर आधारित रिपोर्ट में पाया गया कि कंपनियां कुशल लोगों को तरजीह देने से पीछे नहीं हट रही हैं। उदाहरण के लिए, अति विशिष्ट नौकरियों के लिए वेतन में बढ़ोतरी 11 फीसदी से 12 फीसदी के बीच है। इसके अलावा, शहरों के लिहाज से देखा जाए तो इस मामले में, अहमदाबाद, बेंगलूरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और पुणे 12 प्रतिशत या उससे अधिक की बढ़ोतरी के साथ वेतन भुगतान करने वाले प्रमुख शहरों में से एक थे। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि अधिकांश क्षेत्र कोविड की वजह से बनी मंदी की स्थिति से उबर चुके हैं और 17 क्षेत्रों में से 10 ने 7-10 प्रतिशत की प्रगति दर का संकेत दिया है, बाकी 5.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहे हैं।

को-लोकेशन केस में राहत नहीं:चित्रा और आनंद की जमानत याचिका खारिज, सीबीआई ने कहा- बेल मिली तो सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है

नई दिल्ली

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण और पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिस आनंद सुब्रमण्यम को स्पेशल सीबीआई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने गुरुवार को ह्स्श्व को-लोकेशन स्कैम केस में दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई मई 2018 से इस मामले की जांच कर रही है। रामकृष्ण और सुब्रमण्यम दोनों तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है। को-लोकेशन में ब्रोकर्स को एक्सचेंज के सर्वर के करीब अपने सिस्टम और ऑपरेट करने के लिए जगह दी जाती है। एक्सचेंज सर्वरों के पास होने की वजह से ऐसे ब्रोकरों को दूसरों की तुलना में फायदा मिल जाता है क्योंकि डाटा ट्रांसमिशन में कम वक्त लगता है। को-लोकेशन की सुविधा वाले ब्रोकर्स के ऑर्डर एक्सचेंज तक उन ब्रोकर्स की तुलना में जल्दी पहुंच जाते हैं, जिनके पास यह सुविधा नहीं है।

सीबीआई ने कहा- जमानत मिलने से सबूतों से छेड़छाड़ संभव

सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि दोनों ही आरोपी प्रभावशाली पदों पर थे जिस कारण सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। जमानत देने से जांच भी प्रभावित हो सकती है। हाल ही में, रामकृष्ण पर सेबी ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।

हिमालय के योगी के साथ अहम जानकारियां शेयर की

बीते दिनों 6 साल की जांच के बाद SEBI ने 190 पन्नों की रिपोर्ट जारी की थी। इसमें कहा गया था कि एमडी और सीईओ रहने के दौरान चित्रा ने हिमालय के किसी योगी के साथ NSE की कई अहम जानकारियां शेयर की थी।

Motorola Edge 30 : दुनिया का सबसे पतला और सबसे हल्का 5जी स्मार्टफोन हुआ लॉन्च

नई दिल्ली

आजकल स्मार्टफोन काफी स्लीक और कम वजन वाले आने लगे हैं, और ग्राहक भी इन्हें खरीदने में पीछे नहीं है। मार्केट के इन बढ़ते हुए ट्रेड को देखते हुए अब Motorola ने अपना नया स्मार्टफोन 'Edge 30' को लॉन्च कर दिया है, कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का सबसे पतला और भारत का सबसे हल्का 5त्र फोन है। इतना ही नहीं इसका डिस्प्ले 144H5 रिफ्रेश के साथ आता है। यह फोन की मोटाई 6.7mm है। Motorola Edge 30 का डिस्प्ले और फीचर्स

डिजाइन के मामले में नया Motorola Edge 30 काफी अच्छा स्मार्टफोन है, और इस फोन के फ्रंट और रियर पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है इसके अलावा इस फ़ोन के बैक पैनल पर मैट फिनिश देखने को मिलती है। यह फोन IPz2 रेटिंग के साथ आता है

जिससे पानी से बचाव होता है। इ फोन में 6.5-इंच का POLED डिस्प्ले दिया गया है। जिसमें 2400 & 1080 पिक्सल रेजलूशन और 144H5 का बेहतरीन रिफ्रेश रेट मिल जाता है। यूजर्स को इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

दमदार प्रोसेसर

परफॉरमेंस के लिए इस फोन में इंडिया का पहला Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G प्रोसेसर लगा है। पावर के लिए इस फोन में 4,020mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W टर्बो फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट प्रदान करती है। यह फोन ह्रु की बात करें तो फोन Android 12 पर काम करता है।

पावरफुल कैमरा

फोटोग्राफी के लिए नए Motorola Edge 30 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप लगा है। जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का अल्ट्रावाइड सेंसर और 2MP का डेप्थ सेंसर दिया है। इसके अलावा सेल्फी के लिए इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। बेहतर साउंड के लिए इस फोन में डॉल्बी एटमॉस के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर, 5G बैंड सपोर्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

कीमत और उपलब्धता

नए Motorola Edge 30 को दो वेरिएंट में उतारा गया है जिसमें इसके 6 GB+ 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये है और8 GB+ 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये है। यह फोन ग्रे औ ग्रीन कलर ऑप्शन में आता है। इस फोन की बिक्री 19 मई से ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर होगी। HDFC बैंक यूजर्स को 2000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी देगी।

इंटीग्रेटेड ट्रेड डेव्हेलप सेंटर न्यूज के लिए मालिक, मुद्रक एवं प्रकाशक राधिका वीरेंद्र, स्वामी- इंटीग्रेटेड ट्रेड डेव्हलपमेंट सेंटर इंडिया ईप्रेस द्वारा साई प्रिंटर्स, 91 जहांगीराबाद भोपाल से मुद्रित करवाकर, श्री परिसर, 23 पश्चिम निशातपुरा, डीआईजी बंगला, भोपाल से प्रकाशित। संपादक- राधिका वीरेंद्र। आरएनआई क्र. MPHIN/2018/77221, फोन- 0755-42223334, पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल होगा।)